

गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा

● आज 11.30 बजे नई कैबिनेट की शपथ; नए चेहरों पर फोकस, दो डिटी सीएम हो सकते हैं

गांधीनगर, एजेंसी। गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। सीएम भूपेंद्र पटेल कुछ देर में राज्यपाल को मंत्रियों का इस्तीफा सौंपेंगे। कल गांधीनगर में सुबह 11.30 बजे नई कैबिनेट का शपथ समारोह होगा। नई कैबिनेट में 2 डिटी सीएम बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। गुजरात की मौजूदा कैबिनेट में सीएम पटेल समेत 17 मंत्री थे, जिसमें आठ कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री (स्तर) हैं। गुजरात विधानसभा में 182 विधायक हैं। इस लिहाज से गुजरात सरकार में सीएम समेत 27 मंत्री हो सकते हैं। जिन

कैबिनेट मंत्री		
भूपेंद्र पटेल सीएम	कानुभाई मेहता उप-सीएम	कानुभाई मेहता उप-सीएम
कानुभाई मेहता उप-सीएम	कानुभाई मेहता उप-सीएम	कानुभाई मेहता उप-सीएम
कानुभाई मेहता उप-सीएम	कानुभाई मेहता उप-सीएम	कानुभाई मेहता उप-सीएम
राज्यमंत्री एवं राज्य प्रभार		
कानुभाई मेहता राज्यमंत्री	कानुभाई मेहता राज्यमंत्री	कानुभाई मेहता राज्यमंत्री
कानुभाई मेहता राज्यमंत्री	कानुभाई मेहता राज्यमंत्री	कानुभाई मेहता राज्यमंत्री
कानुभाई मेहता राज्यमंत्री	कानुभाई मेहता राज्यमंत्री	कानुभाई मेहता राज्यमंत्री

विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, उन्हें फोन कर सूचना दे दी गई है। शपथ समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस से आए नेताओं को मिल सकता है मंत्रीपद : नए मंत्रिमंडल में 16 में से 7-10 मंत्रियों को ड्रॉप और 3-5 मंत्री रिपीट किए जा सकते हैं। नए चेहरों में कांग्रेस से आए अर्जुन मोहवाडिया, अल्पेश ठाकोर, सीजे चावड़ा और हार्दिक पटेल को मौका मिल सकता है। सीराष्ट्र से जयेश वर्दडिया और जीतू वाघानी को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। खासकर पाटीदारों और उत्तर गुजरात से ठाकोर समुदाय को तवज्जो दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन राज्य मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है, उनमें मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, पंचायत मंत्री बच्चूभाई खाबर, वन एवं पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भीखुसिंह परमार और आदिवासी विकास मंत्री कुंवरजी हलपति शामिल हैं।



नंदयाल/कुर्नूल, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्रप्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत 'विकसित भारत बन चुका होगा। मैं दावे से कहता हूँ कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। आज दुनिया, भारत को 21वीं सदी के नए मैनुफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। इस सफलता का सबसे बड़ा आधार है, आत्मनिर्भर भारत का विजन। हमारा आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर

पीएम मोदी बोले- 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की होगी

आज दुनिया हमें मैनुफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही, वजह आत्मनिर्भर भारत का विजन



मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी साथ थे। यहां मेडिटेरियन हॉल है, जिसके चारों कोनों पर चार मशहूर किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल बने हैं। इसके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की

आशीर्वाद मिल रहा है। मोदी ने कहा अभी दो दिन पहले ही गुगल ने आंध्र प्रदेश में बड़े निवेश की घोषणा की है। गुगल आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रहा है। कल जब मैं गुगल के सीईओ से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिका के बाहर दुनिया भर के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन अब हम आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। इस नए एआई हब में शक्तिशाली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर क्षमता, बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्रोत और विस्तारित फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क शामिल हैं। एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे बनाया जाएगा।

नारायण-सुधा मूर्ति का जाति जनगणना में शामिल होने से इनकार

सर्वर से कड़ा- हम पिछड़े वर्ग से नहीं; कर्नाटक सरकार बोली- मजबूर नहीं कर सकते

बेंगलूर, एजेंसी। इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना में भाग लेने से इनकार कर दिया है। कुछ दिन सर्वे करने वाले लोग उनके घर गए थे, तो उन्होंने कहा- हम अपने घर पर सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार करते हुए एक घोषणापत्र पर साइन किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा- हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं। इसलिए, उन समुदायों के लिए कड़ा जा रहे सरकार के सर्वे में भाग नहीं लेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सुधा मूर्ति और उनके परिवार के रुख पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- सर्वे में भाग लेना या न लेना ऑप्शनल है। अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता है तो हम किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

पंजाब में 5 लाख रिश्तत लेता डीआईजी गिरफ्तार

सीबीआई ने मोहाली ऑफिस से पकड़ा, चंडीगढ़ में घर पर भी रेड; कारोबारी से मांगी घूस

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब में रोपड़ रेंज के छद्म हरचरन सिंह भुखर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिश्तत लेते रगे हाथ पकड़ा है। उसने मंडी गोबिंदगढ़ के स्कूप कारोबारी से 5 लाख रिश्तत मांगी थी। कारोबारी ने CBI को शिकायत दी। इसके बाद CBI ने ट्रैप बिछाया। गुरुवार को कारोबारी पेसे लेकर मोहाली स्थित ऑफिस से पहुंचा था। यहीं से टीम ने भुखर को पकड़ लिया। ऑफिस के साथ CBI की टीम उसके चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में स्थित घर में पहुंची है। जहां जांच जारी है। भुखर को कल चंडीगढ़ में CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। भुखर विभिन्न जिलों में SSP रह चुका है। रोपड़ रेंज में तैनाती के दौरान ही कई अवैध कार व्यापार के मामले सामने आए थे, जहां चेसिस नंबर बदलकर स्कूप गाड़ियां बेची जा रही थीं। सूत्रों के मुताबिक भुखर इन मामलों को दबाने के लिए रिश्तत लेता था। हरचरन सिंह भुखर 2007 बैच का IPS अधिकारी है। 27 नवंबर 2024 को उसे रोपड़ रेंज का DIG लगाया गया था। अवैध कार कारोबार चलाने के बदले 5 लाख रुपए मांगे : स्कूप कारोबारी ने शिकायत में बताया था कि भुखर ने उसके अवैध कार व्यापार को जारी रखने के बदले मासिक रिश्तत मांगी थी। DIG ने पहले 2 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बाद में इसे 5 लाख तक बढ़ा दिया।

अहमदाबाद प्लेन-क्रैश पायलट सुमीत सभरवाल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

याचिका में कहा- जांव एजेंसी पर भरोसा नहीं, कोर्ट की निगरानी में जांव कराई जाए

नई दिल्ली, एजेंसी। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की जांच को लेकर पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल और इंडियन पायलट्स फेडरेशन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि वे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा खो चुके हैं। इसलिए हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की निगरानी में जांच या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की मांग की है।

कर्नाटक कांग्रेस विधायक बोले- अधिकारी प्रेनेंसी का बहाना बनाती हैं

● मीटिंग में नहीं आती, पूछे तो कहती हैं डॉक्टर के पास जाना है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती

चेन्नई, एजेंसी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक शिवांगा बसवराज ने एक महिला अधिकारी पर विवादित कमेंट कर दिया। विधायक राज्य में डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी एक रिव्यू मीटिंग ले रहे थे। जिसमें वन रेंज अधिकारी श्वेता शामिल नहीं हुईं। फिर विधायक ने मीटिंग में सभी के सामने कहा कि अगर वे (अधिकारी) प्रेनेंट हैं, तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? वह पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें बैठकों के लिए बुलाया जाता है, तो वह छुट्टी ले लेती हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती। 6 दिन पहले कर्नाटक सरकार ने पीरियड लीव पॉलिसी मंजूर की कर्नाटक सरकार ने 9 अक्टूबर को पीरियड लीव पॉलिसी 2025 अफूव कर दी है। इससे सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने

राजद-कांग्रेस पर योगी का निशाना

अब कोई भी बिहार को पुराने लालटेन युग में नहीं ले जा पाएगा : योगी आदित्यनाथ

पटना, एजेंसी। भाजपा के नेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा के चुनावी रण में उतर चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को दूसरी जनसभा सहरसा में की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार को आज जब मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे, एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, वाटरवे के रूप में पहचान मिल रही है तो इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद)-कांग्रेस ने शिगूफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। इससे यह लोग फर्जी मतदान करार गरीबों-दलितों के हकों पर छेकती डाल सके। चुनाव में यह विकास की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बिहार अब पुराने लालटेन युग में नहीं जाएगा, नीतीश जी (मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) इसे एलंडी की दूधिया लाइट में लेकर आगे बढ़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां नामांकन रैली में सहरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार आलोक रंजन झा, सोनबरसा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक

ट्रेन में अब बेडरोल में कंबल के साथ मिलेगा कवर

● जयपुर-असर्वा एक्सप्रेस के एसी पैसंजर्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली, जयपुर, एजेंसी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार से राजस्थान के खातीपुरा जयपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर-असर्वा एक्सप्रेस के एसी क्लास पैसंजर्स के लिए कंबल कवर की सुविधा शुरू की है। यह पायलट प्रोजेक्ट है, जो सफाई और हाइजीन सुधारने के लिए लाया गया है। सभी एसी कोच के यात्रियों को प्रिंटेड कंबल कवर मिलेंगे, ताकि गंदे कंबल और बदबू आने की शिकायत न मिले। रेल मंत्री ने कहा कि अगर यह सुविधा सफल रही तो पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने जानकारी दी थी कि एसी कोच में बेडरोल में मिलने वाले कंबल को हर महीने धोया जाता है। पहले बेडरोल किट में एक्सट्रा बेडशीट दी जाती थी, जो क्लिंट कवर की तरह इस्तेमाल होती थी। मंत्री बोले- सफाई को लेकर संशय रहता था : रेल मंत्री ने कहा कि कंबल का इस्तेमाल सालों से हो रहा है, लेकिन सफाई को लेकर संशय

सरकार ने फूड-ड्रिंकिंग प्रोडक्ट पर ORS लेबल के नियम बदले

कंपनियां WHO से फार्मूला मंजूर होने के बाद लेबल लगा सकेंगी; 2022-24 के आदेश रह किए

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्था (FSSAI) ने कहा कि यदि किसी फूड-ड्रिंकिंग प्रोडक्ट का फार्मूला विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मंजूर न किया गया हो तो कंपनी उस प्रोडक्ट पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) का लेबल नहीं लगा सकेगी। सभी कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स से ORS लेबल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार के 2022 और 2024 के आदेश में कंपनियों को अपने प्रोडक्ट में ORS शब्द जोड़ने की अनुमति दी गई थी जैसे प्रीफिक्स (शुरू में) या सफिक्स (अंत में)। इसके बाद कुछ फसूट ड्रिंक, नॉन-कार्बोनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ ORS का लेबल लगाने लगे थे। हालांकि, तब शर्त रखी गई थी कि उस प्रोडक्ट पर साफ लिखना होगा कि उत्पाद WHO द्वारा अनुशंसित ORS फार्मूला नहीं है। अब FSSAI ने इन पुराने आदेशों को पूरी तरह रद्द कर दिया

अबकी बार पर्यावरण संग उत्सव, सात साल बाद दिल्ली के लोगों को आतिशबाजी की मिली अनुमति

दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के लोग करीब सात साल बाद दीपावली पर पटाखे जला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिलने के बाद दिल्लीवासी बेहद खुश हैं। इससे उत्साहित दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोर्ट का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये निर्णय देश की सांस्कृतिक संवेदनाओं और जनभावनाओं को समझने वाला कदम है, जो परंपरा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच सुंदर संतुलन स्थापित करता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंचने के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015-16 से ही पटाखों पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिल्ली एनसीआर में पारंपरिक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई।

अदालत ने यह माना कि पटाखे प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक हैं। इनके प्रयोग पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। तब से दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध रहा। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर 19 और 20 अक्टूबर



को सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त छूट दी है। दिल्ली सरकार की ओर से अधिकृत विक्रेता ही ग्रीन पटाखे बेचेंगे। फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि अभी उसने किसी को भी ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी है। जल्द ही विश्वसनीय और सक्षम विक्रेताओं को अधिकृत लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए बुधवार शाम को मंत्री ने दिल्ली के तमाम पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक की है।

दिल्ली सरकार कराएगी कोर्ट के

निर्देशों का पालन : बुधवार को सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार ज्यादातर दुकानदारों को लाइसेंस देगी, ताकि ग्रीन पटाखों की कालाबाजारी न हो। सबको आसानी से पटाखे उपलब्ध हों। दिल्ली पुलिस, एमसीडी, डीपीसीसी, सीपीसीबी सहित दिल्ली सरकार की अन्य जिम्मेदार एजेंसियां ग्रीन पटाखों की बिक्री, इन्हें जलाने के समय, कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगी। उन्होंने दिल्लीवासियों से सरकार के साथ मिलकर नियमों का पालन कराने में

सहयोग करने की अपील भी की है। मंत्री ने कहा है कि लोगों के सहयोग से दीपावली के पर दिल्ली की हवा बेहतर रही तो ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति आगे भी जारी रहेगी।

नीरी से प्रमाणित, क्यूआर कोड लगे ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे: दिल्ली सरकार ने साफ निर्देश दिये हैं कि केवल नीरी की ओर से प्रमाणित क्यूआर कोड लगे ग्रीन पटाखे ही दुकानदार बेच पाएंगे। इनकी बिक्री 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिन तक की जा सकेगी। ग्रीन पटाखों की बिक्री के स्थान और बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त जल्द ही तय करेंगे। सभी जिलों में अधिक दुकानों को लाइसेंस दिए जाएंगे। दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की सुप्रीम कोर्ट से छूट मिलने के बाद पर्यावरण मंत्री ने डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल, दिल्ली पुलिस के चेयरमैन संदीप कुमार और पीईएसओ, विशेष आयुक्त रविंद्र यादव, डीपीसीसी के संस्थान सीएसआईआर नीरी ने ग्रीन पटाखे विकसित किए। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग को सशर्त अनुमति दी थी।

को लागू करने की तैयारी की। पीईएसओ प्रमाणित पटाखा विक्रेताओं के साथ भी मंत्री ने बैठक की। मंत्री ने कहा, इस दीपावली पटाखा विक्रेता भी सरकार के अभियान का हिस्सा रहें। वे लोगों को बताएंगे कि केवल ग्रीन पटाखे ही मान्य हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनके उपयोग का समय सिर्फ दो घंटे रात में 8 से 10 बजे और एक घंटा सुबह 6 से 7 बजे तय किया है। यह छूट फिलहाल अस्थायी है, लेकिन अगर दिल्ली ने अनुशासन और जागरूकता दिखाई तो यह स्थायी भी हो सकती है।**एक्यूआई रिपोर्ट सीपीसीबी, सुप्रीम कोर्ट रोज जाएगी** :मंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) 14 से 25 अक्टूबर तक हर दिन एक्यूआई स्तर की निगरानी करेगी। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। कोर्ट के निर्देश का पूरा पालन किया जाएगा। साल 2018 में वैज्ञानिक संस्थान सीएसआईआर नीरी ने ग्रीन पटाखे विकसित किए। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग को सशर्त अनुमति दी थी।

डीयू वीसी इंटरनशिप स्कीम के लिए 2280 छात्र शॉर्टलिस्ट ,ग्रुप डिस्कशन समाप्त



दिल्ली, एजेंसी । दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की वाइस चांसलर (VC) इंटरशिप स्कीम पार्ट टाइम 2025-26 के लिए 2280 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस बार 3500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें 2280 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

15 अक्टूबर को ग्रुप डिस्कशन हुआ समाप्त : आवेदकों को 13 से 15 अक्टूबर तक ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। यह प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। आगामी दिनों में चर्यान्त उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। चयन के बाद वीसी इंटरशिप के लिए छात्रों को डीयू के 55 से अधिक विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। डीयू ने वर्ष 2022-23 में इस स्कीम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य डीएसडब्ल्यू कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को इंटरशिप के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इससे छात्रों को विश्वविद्यालय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों और सामान्य रूप से सरकारी व्यवस्थाओं में आधिकारिक कामकाज को समझने में मदद मिलती है। डीएसडब्ल्यू कार्यालय दो प्रकार की इंटरशिप प्रदान करता है। शैक्षणिक सत्र के दौरान छह महीने के लिए वीसी इंटरशिप स्कीम पार्ट टाइम और गर्मी की छुट्टियों के दौरान दो महीने के लिए फुल टाइम ग्रीष्मकालीन इंटरशिप उपलब्ध कराता है।

प्रति सप्ताह 8-10 घंटे करना पड़ता है काम : प्रति सप्ताह पार्ट टाइम इंटरशिप के दौरान प्रति सप्ताह 8-10 घंटे काम करना पड़ता है। इसके लिए चर्यान्त छात्र को 5775 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है। जबकि ग्रीष्मकालीन इंटरशिप के लिए प्रति सप्ताह 20 घंटे कार्य करना होता है। इसके लिए 11 हजार रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है।

दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 कॉलेजों को दी 108 करोड़ की सौगात, अब तक तीन किस्तों में दिए 325 करोड़ रुपये

दिल्ली,एजेंसी । दिल्ली सरकार ने डीयू से संबद्ध 12 कॉलेजों को 108 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी की है। अब तक सरकार कुल 325 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी कर चुकी है, जिससे कॉलेजों के विकास और स्टाफ के वेतन में राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 वित्तपोषित कॉलेजों को वित्तीय सहयोग देने के लिए वर्ष 2025-26 की तीसरी किस्त के रूप में 108 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। अब तक तीन किस्तों में कॉलेजों को 325 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी गई है। सूर ने कहा कि अगर शिक्षण संस्थान वित्तीय रूप से समृद्ध नहीं होंगे तो उनमें अच्छे और काबिल छात्र नहीं बन पाएंगे। इन उपहार दिया है।

प्रशासन की निगहबानी को धता बता हर साल होती रही आतिशबाजी, दिवाली पर जमकर फोड़े जाते रहे पटाखे

नई दिल्ली, एजेंसी। पटाखों पर कोर्ट ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन 7 साल तक लगी रोक के दौरान भी राजधानी में हर दिवाली पटाखों की गूंज सुनाई देती रही। इसके लिए प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठना लाजिमी है। एक और वजह दिल्लीवासियों का पटाखों की परंपरा से खुद को अलग न कर पाना भी है। वर्ष 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर रोक लगाई और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी, तो उम्मीद थी कि इससे वायु गुणवत्ता सुधरेगी। लेकिन इसके पालन में लापरवाही और नियंत्रण की कमी से हर दीपावली पर एक्यूआई की स्थिति खराब होती रही। दिल्ली पुलिस हर साल बड़ी



मात्रा में अवैध पटाखे बरामद करती है, लेकिन दीपावली पर सस्ते और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर लगाम लगती नहीं दिखती। वर्ष 2020 में एनजीटी ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया, तब भी स्थिति में खास बदलाव नहीं आया। प्रतिबंध के बावजूद दिवाली की

रात पटाखे फूटे, और शादी-ब्याह में भी आतिशबाजी आम रही। दिल्ली के निवासी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुरु ग्राम, झज्जर, रोहतक, गाजियाबाद और नोएडा से पटाखे खरीदकर लाते रहे।

रसगुल्लों में कीड़े और गाय के घी के पैकेट में मिली मिलावट, गोरखधंधा करने वालों पर कार्रवाई

नोएडा, एजेंसी । शहर में मिलावटखोरों पर कार्रवाई जारी है। बुधवार को खाद्य विभाग ने कीड़े मिलने पर 110 किग्रा रसगुल्लें को नष्ट करा दिया। वहीं गाय का घी पैक करने वाली कंपनी से 128 किलो मिलावटी घी जब्त की गई है। विभाग की ओर से रसगुल्लें और घी के साथ कुल 10 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेक्ष मिश्रा ने बताया कि बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी मालती ने दनकोर पनीर भंडार से पनीर का नमूना लिया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार, विशाल गुप्ता, रविंद्र नाथ वर्मा और



अमर बहादुर सरोज की टीम ने सेक्टर डेल्टा वन स्थित बाबू रतन मिश्रन भंडार से कलाकंद का नमूना लिया।

टीम ने मंगलवार देर रात जेवर

टोल प्लाजा पर अलीगढ़ की तरफ से आने वाली पनीर और दूध की गाड़ियों की जांच की। मौके से मधु डेयरी मधुपुर के दूध के टैंकर से दूध का नमूना लिया।

भूकंप से दहला इंडोनेशिया, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7 रिकॉर्ड



जकार्ता, एजेंसी। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि गुरुवार को इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 70 किलोमीटर (43.5 मील) की गहराई में था।

पैसिफिक सुनामी वॉरनिंग सेंटर ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की है। यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र अंबेपुरा शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था, जिसकी आबादी 62,000 से ज्यादा है। इंडोनेशियाई मौसम विज्ञान विभाग, इंडोनेशियाई मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी यानी बीएमकेजी के अनुसार, भूकंप 6.6 तीव्रता का था, जो सारमी-पापुआ से 61 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था।

इससे पहले, 10 अक्टूबर को, दक्षिणी फिलीपींस के तट पर दो शक्तिशाली भूकंप आए थे,

जिसके बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी और भूकंप केंद्र के पास के शहरों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था।

विशाल द्वीप समूह वाला देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। जिस वजह से यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं और यह जापान से दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए प्रशांत बेसिन तक फैला रहता है।

जनवरी 2021 में सुलावेसी में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप में 100 से अधिक लोग मारे गए थे जबकि हजारों बेघर हो गए थे। इससे पहले 2018 में पापु में 7.5 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में 2 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2004 में आंचे प्रांत में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था।

बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह कराने के समय पर राजनीतिक दलों में गतिरोध

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने के समय को लेकर राजनीतिक असहमति अंतरिम सरकार धर्मसंकट में है। संकेत हैं कि मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस जल्द ही निर्णायक हस्तक्षेप कर सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी में होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा है। इसके उलट बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) जैसी पार्टियां जनमत संग्रह चुनाव से पहले कराने की मांग कर रही हैं। जमात और एनसीपी का तर्क है कि चार्टर पर जनता की राय मतदान से पहले जाननी चाहिए।

ढाका टिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार कल (शुक्रवार) जुलाई के राष्ट्रीय (जुलाई) चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाली है इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेदों को पाटने और हस्ताक्षर से पहले अनिश्चितता को दूर करने के प्रयास में सर्वसम्मति आयोग के अध्यक्ष डॉ. यूनुस ने बुधवार को प्रमुख राजनीतिक दलों और गठबंधनों के नेताओं से चर्चा की। चर्चा के बाद वामपंथी गठबंधन ने अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए घोषणा की कि वह चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।



एनसीपी नेता अख्तर हुसैन ने कहा कि जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर करने के पार्टी के फैसले की समीक्षा की जा रही है। बताया गया है कि अंतरिम सरकार के विभाग भी जनमत संग्रह की समय-सीमा को लेकर विभाजित हैं। जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर समारोह कल राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में निर्धारित है। इसमें कम से कम 30 राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद है। जनमत संग्रह का मूल

प्रस्ताव राष्ट्रीय सहमति आयोग का है। अब आयोग अंतरिम सरकार को संभावित तिथियों का सुझाव देते हुए एक औपचारिक पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉ. बदीउल आलम मजूमदार ने पुष्टि की है कि अभी तक समय सीमा तय नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा, हमने जनमत संग्रह कब होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने के समर्थकों

का कहना है कि इससे राजनीतिक दलों को जनता की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा।

इस मसले पर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की अध्यक्षता में स्थायी समिति ने सोमवार रात बैठक की। पार्टी ने अपने रुख की पुष्टि की कि जनमत संग्रह राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही होना चाहिए। महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और स्थायी समिति

के सदस्य सलाहद्वीन अहमद सहित बीएनपी नेताओं ने शीघ्र जनमत संग्रह के विचार को चुनाव में देरी की एक चाल बताकर खारिज कर दिया ।

फखरुल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार सहमत शर्तों से पीछे हटती है तो बीएनपी जनमत संग्रह और चुनाव दोनों का बहिष्कार कर सकती है। संविधान सुधार आयोग के एक सदस्य ने संकेत दिया कि एक धर्म-आधारित पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव में देरी करना चाह रही है। जमात महासचिव प्रो. मिया गुलाम पोरवार ने टकराव की बजाय बातचीत का आग्रह करते हुए सुलह का स्वर अपनाया है। उन्होंने आम सहमति में बाधा डालने वाले एक राजनीतिक नेता के अहंकार की भी आलोचना की।

बीएनपी और गणतंत्र मंच के नेताओं ने कहा कि डॉ. यूनुस इस मुद्दे पर काफी हद तक चुप रहे हैं। हालांकि, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यात्रा से लौटने के बाद वह कथित तौर पर काफी मजबूत स्थिति में हैं। बीएनपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, अगर डॉ. यूनुस जनमत संग्रह पर जल्दबाजी में राजपत्र जारी कर देते हैं तो राजनीतिक दलों के पास पैतरेबाजी करने की बहुत कम गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि अगर वे सहयोग करने से इनकार करते हैं तो उन्हें और सख्ती से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

सियासी संकट की कगार पर फ्रांस दो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, जा सकती हैं मैक्रों की साा

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस एक नए राजनीतिक संकट की कगार पर खड़ा है, जहां प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू के नेतृत्व वाली सरकार को राष्ट्रीय सभा में दो अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रस्ताव पास हो गए, तो राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के पास केवल एक विकल्प बचता है- संसद भंग करके नई चुनाव कराना। अविश्वास प्रस्ताव मैक्रों के कट्टर विरोधियों द्वारा दायर किए गए हैं, हाई-लेफ्ट पार्टी फ्रांस अनर्बॉन्ड और दाहिने के नेशनल रेनैली की नेता मरीन ले पेन अपने सहयोगियों के साथ। अगर लेकोर्नू सहायक रहते हैं, तो यह नजदीकी वोटिंग हो सकती है, लेकिन



हारने पर राष्ट्रपति संसद भंग करने का रास्ता अपना सकते हैं।

क्यों और किसने प्रस्ताव दायर किया

ले पेन ने लंबे समय से नए विधानसभाई चुनाव की मांग की है

और पोल में उनके पक्ष में समर्थन दिख रहा है। उनके सहयोगी एरिक सियोटी के साथ मिलकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि संसद भंग करना देश को संकट से निकालने का सबसे लोकतांत्रिक और प्रभावी तरीका है। फ्रांस अनर्बॉन्ड पार्टी का प्रस्ताव भी इसी दिन दायर हुआ, जिसमें कहा गया कि लेकोर्नू को हटाना मैक्रों को भी सत्ता से हटाने की दिशा में मदद कर सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ने साफ किया है कि वह 2027 तक अपने कार्यकाल को समय से पहले समाप्त करने का इरादा नहीं रखते।

नेपाल: निर्वाचन आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में आम चुनाव के लिए जरूरी तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देश की अंतरिम सरकार ने 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की घोषणा की है।



निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बैठक में उन 29 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है जो पिछले संघीय संसद, प्रदेश सभा और स्थानीय चुनाव में कम से कम एक भी सीट पर जीत हासिल की थी। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने कहा कि सभी दलों से निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की गई है। इस समय पूरे देश में मतदाता नामावली संकलन का काम चल रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी: भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं 1.4 करोड़ लोग

जिनेवा, एजेंसी । संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी ने बुधवार को कहा कि उसके प्रमुख दानदाताओं द्वारा वित्त पोषण में की गई कटौती से छह देशों में उसकी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। उसने चेताया कि इससे करीब 1.4 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि इस वर्ष उसका वित्त पोषण अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है।डब्ल्यूएफपी ने कहा, इस चुनौती का मुख्य कारण अमेरिका (डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत) तथा अन्य प्रमुख पश्चिमी देशों द्वारा अनुदान में की गई भारी कटौती है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि उसकी खाद्य सहायता प्राप्त करने वाले 1.37 करोड़ लोगों को अब आपात स्तर की भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। जिन देशों में मुख्य व्यवधान देखने को मिल रहे हैं, वे अफगानिस्तान, कांगो, हैती, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान हैं। सभी दलों को इस कार्य में भी सहयोग करने की अपील की गई है।हाल ही में सरकार ने नेपाल में मतदान की उम्र सीमा को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष कर दिया है। नेपाल में जैन जी विद्रोह के बाद गठित अंतरिम सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए निर्वाचन में मतदान करने की उम्र को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष किए जाने का फैसला किया था।इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन तालिका के मुताबिक ही सभी दल अपना पंजीकरण और नवीकरण करा लें। आयोग ने आम निर्वाचन में सहभागिता के लिए नए राजनीतिक दलों को अपना दल पंजीकरण कराने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया है। इसी तरह पुपाने राजनीतिक दलों को भी इसी अवधि में अपने दल का नवीकरण कराने को कहा गया है। यूएफपी ने बताया कि इस साल उसे 40वें कम वित्त पोषण मिलने के आसार हैं।

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में राष्ट्रीय शोध वेबीनार का हुआ आयोजन

नई शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं अनुसंधान पर केन्द्रित है: प्रो. शरद

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली में उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार का विषय नई शिक्षा पद्धति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रहा, जिसमें देशभर से लगभग 284 शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गीता भारती द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उन्होंने अपने उद्घोषण में नई शिक्षण पद्धति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्तमान शिक्षा जगत में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यशाला की सह-संयोजक डॉ. भावना नागेंद्र ने विषय विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों का स्वागत कर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। एकदिवसीय राष्ट्रीय वेबीनार में मुख्य वक्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय



विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से प्रोफेसर शरद कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने शोधार्थियों को नई शिक्षा पद्धति से अवगत कराते हुए रचनात्मक, छात्र-केंद्रित एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षण पद्धति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं अनुसंधान पर केंद्रित है, जिसके कारण विद्यार्थियों में क्रियात्मक क्षमता,

तर्कशक्ति एवं रचनात्मक सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। सह-वक्ता के रूप में गैलगाोटियस विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) से ऑनलाइन जुड़ी डॉ. सुदेशना चक्रवर्ती ने नई शिक्षण पद्धति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर गहन एवं शोधपरक व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य एवं उद्योगों के क्षेत्र

में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, जिससे मानव की सोचने की क्षमता को नया आयाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एवं डेटा प्रोसेस जैसी अवधारणाओं को समझना आवश्यक है तथा शिक्षण एवं अनुसंधान में एआई का एकीकरण समय की मांग है।



राज्यों के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से लगभग 284 शोधार्थियों ने ऑनलाइन भाग लेकर नई शिक्षण पद्धति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विविध पहलुओं पर संवाद किया। वेबीनार में डॉ. सुरेश तिवारी, डॉ. वहीदुन निशा, राजकिशोर तिवारी, सुपमा शुक्ला, डॉ. असलेन्द्र जायसवाल, डॉ. रेनु सिंह, पंकज सिंहल, गुलाब सिंह श्याम, संदीप कुमार कोल, मनीष

सोनी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संयोजन प्रो. सुनील सिंह (आयोजक सचिव) एवं संचालन डॉ. संदीप कुमार शर्मा (सह-संयोजक) द्वारा किया गया। अंत में कार्यक्रम के संयोजक प्रो. बी. एल. सिंह 'आयाम' ने सभी उपस्थितजनों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

रसोइयों का प्रदर्शन, वेतन वृद्धि की मांग; महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर दिया धरना

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्याह्न भोजन योजना की रसोइयों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे 70 से अधिक रसोइयां विधिका भवन परिसर में एकत्रित हुईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांग है कि वर्तमान 4 हजार रुपए मासिक वेतन को बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपए महीने की जाए, ताकि वे जीवन-यापन कर सकें।

महिलाएं बोलीं-सालों से मानदेय में नहीं हुई बढ़ोतरी: प्रदर्शनकारी रसोइयों ने बताया कि वे कई सालों से स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन बना रही हैं, लेकिन उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

रसोइया आनंदी बैस ने कहा कि सुबह से दोपहर तक काम करने के बावजूद 4 हजार रुपए में परिवार का खर्च चलाना असंभव है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी: महिलाओं ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि गैस, राशन और स्कूल आने-जाने का खर्च भी इसी मामूली रकम से उठाना पड़ता है, जिससे उनका जीवनयापन बेहद कठिन हो गया है। अन्य रसोइयों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी वेतन वृद्धि नहीं की गई, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगी।

कोयला ट्रेलर पलटा, ड्राइवर के हाथ-पैर टूटे; यूपी से आ रहा था वाहन

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के जयंत और उत्तर प्रदेश के शक्ति नगर सीमा इलाके में एक कोयले से भरा ट्रिप ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एनसीएल के जयंत नेहरू शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार सुबह करीब 9:30 की है।



कोयला ले जा रहा था।

लोगों की वाहन से बाहर निकाला, अस्पताल में कराया भर्ती: स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और आसपास मौजूद लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, जिस सड़क मार्ग पर

यह हादसा हुआ, वह सिंगल रोड है और इसमें कई मोड़ हैं। अक्सर तेज गति के कारण यहां हादसे होते रहते हैं। चौकी प्रभारी ने बताया कि चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन कई ट्रेलर ड्राइवर जल्दी कोयला सप्लाई के चक्कर में तेज स्पीड से वाहन चलाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं।

समय-सीमा में भू अर्जन मुआवजा भुगतान के लिए विशेष कैंपों का होगा आयोजन

सीधी। डिप्टी कलेक्टर ने जानकारी देकर बताया कि रीवा-सीधी-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना, महान नहर परियोजना, बाणसागर नहर परियोजना, गुलाब सागर परियोजना, संयंत्र टाईगर रिजर्व, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संचालित परियोजनाओं में प्रभावित भूमि एवं उन पर स्थित परिसंपत्तियों का चिह्नंकन कर अवाई पारित किया जा चुका है। पारित अवाई के अनुसार अधिकांश प्रभावितों को मुआवजा भुगतान भी किया जा चुका है। किंतु यदि किहीं कारणों से कुछ प्रभावित हितग्राहियों को मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो उनकी सुविधा एवं परियोजना के समय पर पूर्ण होने के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेष कैम्प का आयोजन आवश्यक है।

एनएसयूआई के प्रदर्शन पर पुलिस चलाई वाटर कैनन प्रदूषण-बेरोजगारी का कर रहे थे विरोध, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट घेराव करने जा रहे थे

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारी प्रदूषण, विस्थापन, बेरोजगारी और छात्र हितों की मांगों को लेकर जमा हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 500 से अधिक छात्र, एनएसयूआई कार्यकर्ता और स्थानीय कांग्रेसी नेता कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे। जब छात्र नेताओं ने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछारें कीं।

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि सिंगरौली जिले में भारी उद्योग और कोयला खदानें होने के कारण गंभीर प्रदूषण है। विस्थापन से प्रभावित लोगों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कि यहां रोजगार के कई अवसर हैं, स्थानीय युवा बेरोजगार हैं क्योंकि कंपनियां सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार का 70 फीसदी स्थानीय रोजगार का दावा खोखला है। चौकसे ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के



सत्ता में आने के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार को डर है कि छात्र संगठन से

गांवों में शुरु हुआ आदिकर्मियों का अभियान सरकारी टीमें कर रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के मझौली विकासखंड में आदिकर्मियों का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दुधमनिया, चंदौहीडोल और अमोहराडोल सहित तीन गांवों के आदिवासी परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य वंचित परिवारों को मुख्यधारा में लाना है।



योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

पात्रतानुसार लोगों से आवेदन करने की अपील: द्विवेदी ने इन गांवों से पहुंचकर ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि यह पहल उन परिवारों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए है, जो अब तक इनसे वंचित थे। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना योजना और पेंशन

मझौली जनपद के सीईओ धनंजय मिश्रा ने बताया कि आदिकर्मियों का अभियान राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य आदिवासी और पारंपरिक समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। वह उड़ीसा से गाजा कि प्रशासनिक टीम लगातार गांवों में सर्वे और जनसंपर्क कर रही है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजनाओं के फायदा से वंचित न रहे।

जनपद सिहावल में दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सकीय बोर्ड शिविर आयोजित - 51 पंजीकरण में 15 प्रमाणपत्र जारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा के मार्गदर्शन में किशोर न्याय समिति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा के पालनार्थ, जिले के समस्त 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 22 सितम्बर से 14 नवम्बर 2025 तक जिलेभर में स्क्रीनिंग एवं चिकित्सकीय बोर्ड शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार 15 अक्टूबर को जनपद सिहावल में चिकित्सकीय बोर्ड शिविर का



आयोजन किया गया, जिसमें कुल 51 बच्चों का पंजीकरण किया गया तथा चिकित्सा परीक्षण उपरांत 15 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(यू.डी.आई.डी. कार्ड) जारी किए गए। शिविर में चिकित्सकीय बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सकों कृ मानसिक रोग विशेषज्ञ, नाक-

कान-गला रोग विशेषज्ञ, औषधि रोग विशेषज्ञ एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ कृ द्वारा परीक्षण कार्य संपादित किया गया। शिविर में जिला दिव्यांग

पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), सीधी की टीम के सदस्य दीपक त्रिपाठी, शिवासु शुक्ला (अंतर्विषयक विशेष शिक्षक) तथा शेषमणि साहू द्वारा संभावित दिव्यांग बच्चों की जांच, दस्तावेज सत्यापन एवं अभिभावकों को यू.डी.आई.डी. कार्ड प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

यह अभियान सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले के सभी विकासखंडों में चरणबद्ध रूप से संचालित किया जा रहा है, ताकि कोई भी दिव्यांग बच्चा शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं से वंचित न रहे।

खदान में डोजर ऑपरेटर की तलाश बंद, एनडीआरएफ और सेना ने 5 दिन बाद रेस्क्यू रोका; परिवार ने मौत स्वीकारी



मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सोहागपुर एरिया में एक निजी कंपनी के कामकाजी स्थल पर मिट्टी धंसने से डूबे डोजर मशीन ऑपरेटर अनिल कुशवाहा की तलाश पांच दिन बाद बंद कर दी गई है। प्रशासन ने परिवार की सहमति से उन्हें मृत मान लिया है। यह हादसा 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे हुआ। दरअसल, आरकेटीसी कंपनी द्वारा फिलिंग के दौरान मिट्टी अचानक फिसल गई। इससे डोजर मशीन और एक हाईवा गहरे पानी में डूब गए। अनिल कुशवाहा रीवा के मऊगंज के निवासी थे।

लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। सेना ने भी वाहन और ऑपरेटर को पानी से निकालने में असमर्थता जताई।

परिवार की सहमति के बाद बंद हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन: कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बताया कि परिवार की सहमति के बाद अनिल कुशवाहा को मृत मान लिया गया है। पुलिस और पंचनामा रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने एसईसीएल या आरकेटीसी द्वारा लगभग 45 लाख रुपए के मुआवजे की राशि तय की है।

45 लाख का मुआवजा एनडीआरएफ के 94 जवानों ने की कोशिश: जिला प्रशासन ने अनिल कुशवाहा की तलाश के लिए वाराणसी से राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) और जबलपुर से सेना की मदद मांगी थी। एनडीआरएफ के 94 जवानों ने प्रयास किए और 84 फीट की गहराई में हाईवा का पता लगाया,

देगी कंपनी: यह इस तरह का पहला हादसा नहीं है। 2014 में भी धनपुरी ओसीएम में मिट्टी भरने के दौरान एक कर्मचारी गहरे पानी में डूब गया था, जिसे निकालने के प्रयास में एक क्रेन और एक गोताखोर भी डूब गए थे। 15 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उन्हें नहीं खोजा जा सका था।

बच्चा चोरी का शक, लड़के को खंभे से बांधकर पीटा; पुलिस ने बताया विक्षिप्त

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के जयंत नेहरू बस्ती इलाके में बच्चा चोरी के संदेह में स्थानीय लोगों ने एक लड़के को खंभे से बांधकर पीटा। गुरुवार को इसका वीडियो सामने आया है। युवक बिहार के गया जिले से काम की तलाश में आया था।

स्थानीय रहवासी विनोद कुमार ने बताया कि गया (बिहार) से आए कुछ लोग बच्चा चोरी की फिराक में घूम रहे थे। जयंत बस्ती के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वीडियो में लोग लड़के से जबरन बच्चा चोरी की घटना कबूल

कराते दिख रहे हैं। पिटाई के बाद लड़के को जयंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़के का कहना है कि वह गया से अपने 7 साथियों के साथ सिंगरौली जिले में काम करने आया था।

जयंत चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार के अनुसार, लड़का विक्षिप्त लग रहा है। वह अपनी पहचान ठीक से नहीं बता पा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी का आरोप सही नहीं है। पुलिस युवक को बाल कल्याण समिति के पास भेज रही है। मामले की आगे की जांच की जा रही है।

अमिलिया में दिव्यांग बच्चों हेतु चिकित्सकीय बोर्ड शिविर आयोजित - 25 पंजीकरण में 08 प्रमाणपत्र जारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा के मार्गदर्शन में किशोर न्याय समिति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा के पालनार्थ, जिले के समस्त 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में दिव्यांगता की त्वरित पहचान एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 22 सितम्बर से 14 नवम्बर तक जिलेभर में जांच एवं चिकित्सकीय बोर्ड शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार 16 अक्टूबर को उप स्वास्थ्य केंद्र,

अमिलिया में चिकित्सकीय बोर्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 25 बच्चों का पंजीकरण किया गया तथा चिकित्सा परीक्षण उपरांत 08 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यू.डी.आई.डी. कार्ड) जारी किए गए। शिविर में चिकित्सकीय बोर्ड के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. रवि पटेल (मानसिक रोग विशेषज्ञ), डॉ. हिमेश पाठक (नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ), डॉ. अमित सिंह (औषधि रोग विशेषज्ञ) तथा डॉ. के. बी. प्रजापति (अस्थि रोग विशेषज्ञ) द्वारा परीक्षण कार्य संपादित किया गया।

जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर गांजा पकड़ा, दमोह का युवक उड़ीसा से ला रहा था; एक लाख का माल जब्त



ईंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी एम. झरिया के नेतृत्व में दो एम. एल.एस. पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान काले रंग का पिड्डू बैग लिए एक युवक पुलिस से देखकर घबरा गया। शक के आधार पर उसकी तलाशी ली गई, तो बैग से 5 किलो से

अधिक गांजा बरामद हुआ। जीआरपी थाना प्रभारी एम. झरिया ने बताया कि नियमित जांच के दौरान युवक संदिग्ध हालत में दिखा। गांजा जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मंदिर आर्थिकी की दिशा में

हिमाचल के मंदिरों का सरकारीकरण पहली बार अपनी संवेदना का कानूनी शब्दकोष पढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ताजा निर्देश वर्षों से चल रही वित्तीय व्यवस्था को नैतिकता व सदाशयता की सीमा बता रहे हैं। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की पीठ ने मंदिर व्यवस्था के उच्चारण बदलते तथा सारी चढ़त के पैमाने तय करते हुए, खर्च करने का मार्गदर्शन किया है। दरअसल मंदिरों की कमाई आज तक

परिभाषित नहीं हुई, जबकि मंदिर आर्थिकी विकसित करने से कई परिवारों को रोजगार, व्यापार को आधार और पर्यटन को चमत्कृत करने का रोड मैप तैयार हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि मंदिर आय की फिजूलखर्ची रुकनी चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि आय के इस स्रोत का सही इस्तेमाल करके हम कम से कम पांच हजार करोड़ की आर्थिकी पैदा कर सकते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर, वैष्णो देवी या शिखड़ी का साई मंदिर अकेले तौर पर ही

पांच से हजार करोड़ की आर्थिकी पैदा कर रहे हैं, तो प्रदेश के कम से कम आठ-दस मंदिर इस हेंसियत में हैं कि आय-व्यय के हिसाब को एक बड़ी आर्थिकी की तस्वीर तक ले जाएं। धूमल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी के सी शर्मा की अध्यक्षता में दक्षिण भारतीय मंदिरों की प्रबंधकीय व्यवस्था पर आधारित एक सिफारिशों रिपोर्ट तैयार की,

लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। नतीजतन मंदिरों का संचालन एक आधी अशुरी व्यवस्था देख रही है। न कोई कर्मचारी कौंडर बना और न ही प्रबंधन का कोई कोड स्थापित हुआ। आश्चर्य तो यह कि मंदिर व्यवस्था का कोई राज्य स्तरीय पैमाना ही नहीं, लिहाजा हर धार्मिक स्थल पर स्थानीय या क्षेत्रीय राजनीति की पहलवानी

होती रही है। मंदिर आय से राजनीतिक खर्चें पूरे होते रहे।

दियोटसिद्ध जैसे मंदिर ट्रस्ट ने अनावश्यक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर रोजगार खरीद लिया, जबकि कई मंदिरों की आय से विकास के नाम पर पैसा जाया होने लगा। माननीय अदालत ने वीआईपी कल्चर की ओर इशारा करते हुए कुछ खर्चें गिनवाए हैं, जहां कानू-किसमिस जैसी खरीद की कड़वाहट घोलती रही है। यहां प्रश्न यह भी तय किया गया कि

मंदिर आय का असली वारिस ईश्वरीय स्थापना है। इसका व्यापक अर्थ यह भी हो सकता कि श्रद्धा में आया धन श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च हो। हमें लगता है कि कानूनी दृष्टि में मंदिर विधेयक को विशिष्टता के साथ आज के संदर्भ में सार्थक बनाने पर बहस होनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रबंधकीय हिसाब से एक केंद्रीय ट्रस्ट या मंदिर विकास प्राधिकरण का गठन करके स्थायी कौंडर व इंतजाम करना होगा।

विश्व शांति का दिव्यास्त्र अहिंसा

कातिलाल मांडेठ

इजराइल हमास युद्ध पर पूर्ण विराम से मध्य पूर्व में शांति

हमास इजराइल में 738 दिन के बाद स्थायी युद्ध विराम के तुरंत बाद सभी बंधकों को छोड़ दिया।इस बीच डेनोल्ड ट्रम्प ने इजराइल संसद को सम्बोधित किया।रिहा हुए इजराइली बंधकों से मिलकर परिजन भावुक हो गए।वह दृश्य वेदना देने वाला था।दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई पर खुशी झलक रही थी।दो साल से इजराइली सेना ने हमास पर हमला किया।हजारो लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए।करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई।लेकिन परिणाम शून्य आया।आज विश्व मे दो सौ देश है।सभी राष्ट्रों का अपना धर्म, अपनी परम्परा और अपनी संस्कृति है।उनके रास्ट्रीय आदर्श है।वे अपने आदर्श नहीं त्यागते है,फिर हमें आदर्श त्यागने की जरूरत क्या है।देश मे हिंसा करने की शासकीय स्वीकृति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर कालिख पोतने के समान है।धर्म को जाने बिना अहिंसा का ज्ञान नहीं हो सकता। हम धर्म को समझकर ही धार्मिक बन सकते है।इदने वर्षों से विदेशों में गृहयुद्ध चल रहे है।लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।सभी युद्धस्त देश ज्यादा उलझते गए है।क्योंकि युद्ध से आज दिन तक कोई समस्या का समाधान होता नहीं दिखा है।क्योंकि हिंसा अन्यायपूर्ण है।ईरान, इराक,इजराइल,हमास,रूस,युक्रेन ,भारत पाकिस्तान आदि अनेक देश युद्ध कर चुके है।लेकिन नतीजा वो ही ढाक के तीन पात वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती दिखाई देती है।कोई भी देश अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए यदि हिंसा का सहारा लेते है तो उनके जैसा मूर्ख कौन होगा।युद्ध को त्यागकर देश के विकास की तरफ ध्यान देना होगा।रूस युक्रेन युद्ध मे क्या खोया क्या पाया।युक्रेन नाटो की मदद से लड़ता रहा और दोनो देश तबाही के दंश झेल रहे है।अपनी मनमानी और जिद्द में दोनो देश बर्बाद हो गए।खरबों डॉलर का धुआं कर सम्पत्ति को राख में बदल करके शांति धारण कर बैठ गए।विश्व शांति का दिव्यास्त्र अहिंसा है।युद्ध स्थायी समाधान नहीं है।आज अहिंसा का स्थान हिंसा ने,आचार का स्थान अनाचार ने और शांति के स्थान पर अशांति ने अपने पैर फैला दिए है।दो देशों के बीच बिगड़ते रिस्ते के साथ ही युद्ध पर उतारू हो जाते है।युद्ध से निर्दोष लोगों की जाने जाती है।जानमाल की क्षति होती है।जीवन मे युद्ध को भूलकर शांति का सुमार्ग ढूंढना है तो हमें सर्वप्रथम धर्म के आगम में उतरना होगा।धर्म को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है।अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है।अहिंसा परम् धर्म है।अहिंसा दिव्यास्त्र है।महात्मा गांधी ने स्वराज पाने का अपना भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन चलाया और उन्हें अपने कार्य मे पूर्ण सफलता भी मिली।कुछ नासमझ लोग हिंसा को सर्वोपरि मानते है क्योंकि वे अहिंसा से परिचित नहीं है।वे कहते है कि आज के युग मे अहिंसा की बात कैसे सोची जा सकती है,

लेकिन अहिंसा तो जीवन जीने की सिख देती है।युद्ध थोपे गए।निर्दोषों के शवों पर राजनीति की गई ,लेकिन भारत और पाकिस्तान, रूस-युक्रेन,ईरान इराक इजराइल और हमास जैसे युद्धस्त देशों के वहा किसी समस्या का समाधान हुआ है।निर्दोष के लहू से सियासत की राजनीति के पीछे सच्चाई कुछ और बयां कर रही है।

धर्म को जानने वाला अहिंसा का पथ कभी नहीं त्याग सकता है।रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन महत्वकांक्षी व्यक्ति है।क्योंकि मन मे अहंकार जागृत हो जाता है तो उसी क्षण मानव की प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाता है।क्योंकि पुतिन को इस बात का अहंकार था कि युक्रेन के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी है।रूस शक्तिशाली देश है।लेकिन चार साल तक युक्रेन ने रूस का बराबर मुकाबला किया तब अहसास हुआ कि मेरी सोच गलत थी।दोनों देश बर्बाद हो गए।क्योंकि जहाँ अहंकार जागृत हो जाता है,वही व्यक्ति स्वयं को शिखर समझने लगता है।हमास ने सबसे पहले इजरायल पर हमला किया।उसके जवाब में इजराइल ने दो साल तक युद्ध थोपे रखा।जब तक अहंकार की हवा भरी हुई रहती है,तब तक आदमी उछलता रहता है।सच्चाई का पता चलेंगा तब अहसास होगा कि जीवन के सुनहरे पल हमने गंवा दिए है।मान और अहंकार ने हम भी इतिहास पढ़ चुके है कि कितने राज्य नष्ट किये है।कितने परिवार नष्ट हुए है।

भारत में आज भी कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे सभी विषय पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के साल 2024-25 के आधिकारिक डेटा के मुताबिक देश के कुल 1,04,125 स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं एवं सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता ही नहीं रहा है बल्कि चिन्ताजनक स्थिति को बयां कर रहा है। ये आंकड़े हमारे शैक्षणिक विकास पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।

एक लाख एकल शिक्षक स्कूलों की त्रासदी से त्रास्त शिक्षातंत्र

-तलित गर्ग -

शिक्षा किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य आज भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक कसक बनकर उभरता है। जब शिक्षा की आत्मा घायल होती है तो राष्ट्र का शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। शिक्षा मंत्रालय के ये हालिया आंकड़े बताते हैं कि एकल शिक्षक स्कूलों में करीब पौने चौतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाना एक भ्रष्टाचार ही है। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? एकल शिक्षक स्कूलों का परिदृश्य भारत के विकास की गैलरी खोलने वाला है। भले ही एकल शिक्षक स्कूलों में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई हो, फिर इतनी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूलों का होना हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी को ही उजागर कर रहा है। यह स्थिति किसी एक आंकड़े की नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की गहरी त्रासदी की तस्वीर है। कल्पना कीजिए-एक शिक्षक जो प्रशासनिक काम भी करता है, मिड-डे मील की निगरानी भी करता है और साथ में सभी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभाता है। क्या वह शिक्षक शिक्षक रह जाता है या व्यवस्था का बोझ उठाने वाला मजदूर बन जाता है? इन बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, जिनके लिए ज्ञान का एकमात्र द्वार ही थकाऊ, उपेक्षा और तंगहाली से भरा है? यह संकेत केवल ग्रामीण भारत तक सीमित नहीं है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ विषय विशेषज्ञों की कमी, प्रयोगशालाओं की अनुपस्थिति और शिक्षण संसाधनों का अभाव है। नई शिक्षा नीति 2020 समग्र शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब आधारभूत ढाँचा ही अपूर्ण हो तो नीतियाँ केवल दस्तावेज़ बनकर रह जाती हैं। हम

2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, पर क्या एकल शिक्षक स्कूलों की यह स्थिति उस दिशा में कोई सार्थक कदम का संकेत है? यह विडंबना है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, जागरण होना चाहिए। यदि 34 लाख बच्चे एकल शिक्षक के भरोसे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनहीनता का प्रमाण है। भारत तभी विकसित होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा-सिर्फ स्कूल में



पर उसके बचपन की शिक्षा का यह हाल है। शिक्षा पर सरकारी व्यय जीडीपी का केवल 2.9 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह 5 से 6 प्रतिशत तक है। जब शिक्षा ही निवेश नहीं बनेगी, तो विकास का आधार कहीं से आएगा? समस्या केवल शिक्षक संख्या की नहीं, बल्कि शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण और संसाधनों की भी है। राज्यों में नियुक्ति प्रक्रियाएँ वर्षों तक लटक रही हैं, स्थानांतरण नीति अव्यवस्थित है, और जो शिक्षक हैं भी, उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति, डिजिटल शिक्षण, नवाचार और नैतिक मूल्य आधारित शिक्षण के प्रशिक्षण से वंचित रखा गया है। यह स्थिति उस समय और अधिक विडंबनापूर्ण लगती है जब हम हर मंच पर नया भारत, विकसित भारत और विश्वगुरु भारत के नारे लगाते हैं। शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखने की आवश्यकता है। रक्षा और स्वास्थ्य की तरह शिक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो, दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों का समुचित समायोजन किया जाए, तकनीक के माध्यम से डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो और शिक्षकों को केवल वृत्तनभोगी कर्मचारी नहीं बल्कि राष्ट्रनिर्माता के रूप में सम्मान मिले। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हमें भारत को पुनः महान बनाना है, तो शिक्षा को पुनः मानवीय बनाना होगा। आज शिक्षा केवल परीक्षा और नौकरी तक सीमित हो गई है, जबकि उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण और विवेक

नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में शिक्षित होगा। अन्यथा, एकल शिक्षक की यह पीड़ा आने वाले भारत की मोन त्रासदी बन जाएगी। शिक्षक दीपक की तरह होते हैं, वे स्वयं जलकर समाज को प्रकाश देते हैं। पर जब दीपक ही अकेला रह जाए, तो अंधकार स्वाभाविक है। अब समय है कि हम इस अंधकार को दूर करने का संकल्प लें, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र का भविष्य है और शिक्षक उस भविष्य के निर्माता हैं। सोचने वाली बात है कि एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएँ कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेलकूल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों एवं योग-व्यायाम जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली इन गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं और ऐसी बीमार बुनियाद पर खड़ा राष्ट्र कैसे स्वस्थ, सक्षम एवं उन्नत होगा? शिक्षा के प्रति यह उपेक्षा हमारे सत्ताधीशों की संवेदनहीनता का भी

संख्या होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति हमारे तंत्र की विफलता को ही उजागर करती है। एक समस्या यह भी है कि शिक्षक जटिल भौगोलिक स्थितियों वाले स्कूलों में काम करने से कतराते हैं। यदि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वे दुरािम से सुगम स्कूलों में अपना तबादला ज्वाइन करने के तुरंत बाद करवा लेते हैं। जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर विभागीय लेन-देन की भी शिकायत होती रहती है। यही वजह है कि शहरों व आसपास के इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत से ज्यादा भी देखी जाती है। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सड़कों पर बेरोजगारों की लाइन लगी है और स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बताया जाता है कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े आठ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। कहने को तो हमारे गाल बजाते नेता भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहते इतराते हैं, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कुठित होती युवा पीढ़ी के लिये उन्होंने क्या ख़ास किया है? नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं है। तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश में ऐसी त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों का होना देश के नीति-निर्माताओं एवं नायकों के लिये शर्म का विषय होना चाहिए।

यदि बंद कमरों में बैठ रहकर काम करने पर, सैर न करने पर, स्वास्थ्यकर भोजन न लेने पर, पूरी नींद न लेने पर या ऐसे ही किसी और कारण से ब्लडप्रेशर हो जाए, शूगर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए तो दवाइयां लेकर भी हम जीवन भर के लिए दवाइयों के गुलाम ही रहते हैं और मजबूरन कई सारे परहेज करने पड़ते हैं।

पीके खुराना

डॉक्टरों के चक्र काटकर, पैसे खर्च करके, जीवन भर के लिए बीमारी मोल लेकर और दवाइयों के गुलाम बनकर अगर हम खुश होते हैं तो यह सुविधा नहीं, हमारी नासमझी है और इस नासमझी पर खुश होने का कोई कारण नहीं है। चुनाव हमारा है कि खुद अपने ही लिए हम रावण बनकर अपना नुकसान खुद करते हैं या आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखकर परमात्मा के दिए इस शरीर का पूरा लाभ उठाकर अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं

हम अक्सर अपने आप में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद ही खुद से अनजान रहते हैं। हमारी अपनी जरूरत क्या है, इसे भी नहीं समझ पाते। आज के समाज में जितनी भी व्याधियां हैं, इनके मूल में हमारा अज्ञान ही तो है। हम इतने मूर्ख हैं कि अपने ही शरीर की आवश्यकताओं के बारे में अनजान हैं, अपने ही मन की आवश्यकताओं के बारे में अनजान हैं। हमारा शरीर और मन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। मन खराब हो तो शरीर सुस्त पड़ जाता है और शरीर

में दर्द हो या बीमारी हो, तो मन स्थिथल हो जाता है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें इन दोनों को जानना और समझना हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। अलग-अलग वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हुआ है कि हमारी पूरी त्वचा सांस लेती है, ऑक्सीजन भीतर खींचती है और कार्बन डाईऑक्साइड बाहर छोड़ती है, सिर्फ हमारी नाक ही नहीं। अगर हमारे शरीर पर मोटा रंग पोत दिया जाए और भीतर-बाहर सांस लेने की सारी संभावना रोक दी जाए और केवल हमारी नाक खुली रहे तो हम शायद तीन-चार घंटे में ही मर जाएं। सिर्फ नाक से काम नहीं चलता, नाक सबसे जरूरी अंग है, लेकिन खुद अकेला नाक ही पर्याप्त नहीं है। हमारा पूरा शरीर लगाभग सात अरब जीवित कोशिकाओं से बना है।

उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, उन सबको कार्बन डाईऑक्साइड बाहर निकालनी है। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे कपड़े इस प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। हमारे कपड़े हमारे मित्र नहीं हैं। लेकिन हजारों वर्षों से कपड़े पहनने के कारण हमारा शरीर दुर्बल हो गया है, बदलते मौसम की भार बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए हमें उन्हें पहनना पड़ता

है। सामाजिक वर्जनाओं के कारण भी वस्त्रहीन रहना संभव नहीं है, पर बीच-बीच में, जब मौसम अनुमति दे और आसपास कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति न हो हमारे वस्त्रहीन होने से जिसकी भावनाएं आहत होती हों, तब वैसे ही, जैसे भगवान ने हमें भेजा था, पूर्णतः वस्त्ररहित रहकर हम जीवन की, यौवन की और ताजगी की एक नयी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। सूरज हमारा मित्र है। हवा हमारी मित्र है। वर्षा हमारी मित्र है। हमारे कपड़े हमारे शत्रु हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम दुर्बल हो चुके हैं, हमें कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। आज का मनुष्य सबसे दुर्बल प्राणी है और कपड़ों को सभ्यता की निशानी मान लिया गया है, इसलिए भी हमें कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। कपड़े पहनें मगर बीच-बीच में शरीर को उसके स्वाभाविक अधिकार का आनंद उठाने का अवसर भी दें। हमारे शरीर में कहीं दर्द हो, हमें जुकाम हो जाए या बुखार हो जाए तो हम फटाफट डाक्टर के पास जाकर दवाई लेना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर का दर्द, जुकाम या बुखार तो सिर्फ संदेशवाहक हैं, वे हमें कुछ बताना चाहते हैं, पर हम हैं कि दवा लेकर संदेशवाहक को ही मार डालते हैं। लंका नरेश दशकंधर रावण ने भी यही किया

था। दशानन रावण के अपने छोटे भाई विभीषण ने रावण को सीख देनी चाही कि वह जनकसुता वैदेही माता सीता जी को दर्यानिधि भगवान रामचंद्र जी के पास सम्मानना वापस भेजकर प्रभु की शरण में चला जाए, परंतु अहंकारी रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। वह मानो ऐसा ही था कि शरीर में दर्द हुआ और डाक्टर के पास जाकर कोई पेनकिलर ले लिया। पवनपुत्र बजरंगबली हनुमान जी ने भी उसे सीख देनी चाही, पर अहंकारी रावण ने क्या किया? दशमुख रावण ने हनुमान जी को साधारण बंदर जानकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। मंजे की बात यह है कि पूंछ में लपेटने के लिए कपड़ा और रस्द रावण के, उस पर लगने वाला धी और तेल रावण का, आग जलाने के लिए अंगार रावण का और लंका जली रावण की। हम भी तो यही करते हैं। बुखार हो जाए तो उसे संदेशवाहक मानने के बजाय हम डाक्टर की फीस पहुंच जाते हैं। अब डाक्टर की फीस भी हम देते हैं, दवा का पैसा भी हम खर्च करते हैं, इस सब में समय भी हम लगाते हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, वह भी हमारी

ही है, जो भविष्य के लिए हमारी सेहत की खराबी का कारण बनती है। हमारा शरीर एक पूरी फार्मसी है, दवाखाना है, लेकिन हम अपने ही शरीर पर विश्वास नहीं करते, शरीर की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते और अज्ञानता तथा लापरवाही के कारण डॉक्टर के पास भारे चले आते हैं। इस अर्थ में अगर देखें तो हम सब भी रावण ही हैं जो खुद ही अपना नुकसान करने पर आमादा हैं। अपनी इस अज्ञानता या अहंकार में हम यह भूल जाते हैं कि सेहत हमारा सबसे बड़ा खजाना है। सेहत है तो हम स्वतंत्र हैं और सेहत खराब हुई तो हम अपने परिवार के सदस्यों की सहायता पर निर्भर हो जाएंगे, या छोटी से छोटी बातों के लिए भी डॉक्टर, नर्स, केयरटेकर आदि पर निर्भर हो जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता बाधित होगी और पैसा खर्च होगा, सो अलग। सैर करना, घूमना-फिरना, पहाड़ों पर जाना, अच्छे भोजन का स्वाद लेना, ये सब कुछ तभी संभव होता है अगर सेहत अच्छी हो। हमारी सेहत वह चाबी है जो कई ताले खोल सकती है। अपनी सेहत की उपेक्षा करके तो हम जीवन में आनंद की उपेक्षा कर डालते हैं, और फिर भी खुद को शिक्षित, सभ्य और सामर्थ्यवान मानते हैं। सुविधा होने पर

रोशनी और हवा का आनंद देना, नियमित सैर अथवा व्यायाम करना, ताजा शुद्ध और स्वास्थ्यकर भोजन लेना हमारी सेहत की गारंटी है। इसके विपरीत यदि बंद कमरों में बैठे रहकर काम करने पर, सैर न करने पर, स्वास्थ्यकर भोजन न लेने पर, पूरी नींद न लेने पर या ऐसे ही किसी और कारण से ब्लडप्रेशर हो जाए, शूगर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए तो दवाइयां लेकर भी हम जीवन भर के लिए दवाइयों के गुलाम बनकर अपना नुकसान खुद करते हैं या आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखकर परमात्मा के दिए इस शरीर का पूरा लाभ उठाकर अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं। यह शिक्षा परिवार से शुरू होनी चाहिए, बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए।

विकास के नाम पर खेल मैदान बना तालाब, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की नई मिसाल

ग्रामीणों में आक्रोश, रोजगार के नाम पर चला मशीनों का खेल, करोड़ों की योजना पर उठे सवाल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। विकास योजनाओं की आड़ में चल रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक और उदाहरण सामने आया है रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम तिवनी से, जहाँ ग्राम पंचायत ने जिस स्थान को कभी खेल मैदान के रूप में विकसित किया था, उसी भूमि पर अब तालाब का निर्माण कर दिया गया है। ग्रामीणों ने इस कार्य को सरासर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का परिणाम बताया है।

सड़कें हुई नष्ट, जलभराव ने बढ़ाई समस्या: तालाब निर्माण के चलते पूर्व दिशा की लगभग 90 प्रतिशत और उत्तर दिशा की 60 प्रतिशत सड़कें जलमग्न होकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इससे न केवल ग्रामीणों की आवाजाही बाधित हुई है बल्कि आसपास के घरों और खेतों में जलभराव की समस्या भी गंभीर रूप से उत्पन्न हो गई है।

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप: ग्रामवासियों का कहना है कि तालाब निर्माण कार्य पूरी तरह से मशीनों के माध्यम से किया गया, जबकि यह कार्य



खेल मैदान से तालाब तक की कहानी

ग्राम तिवनी का यह मैदान वर्षों से खेलकूद का केंद्र रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, यहाँ पिछले लगभग 10 वर्षों तक लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट और अन्य खेल गतिविधियाँ आयोजित होती रही हैं। कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इन आयोजनों के साक्षी रहे हैं। लेकिन पंचायत के हालिया निर्णय ने इस खेल मैदान को तालाब में बदलकर न केवल युवाओं के खेल सपनों पर पानी फेर दिया, बल्कि कई तकनीकी और प्रशासनिक प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं।

मनरेगा के अंतर्गत आने के कारण स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने की बाध्यता थी। इसके बावजूद किसी भी ग्रामीण को वास्तविक रूप से कार्य नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान भी किया गया है, जबकि 25 लाख रुपये से अधिक की राशि मनरेगा फंड से खर्च की गई बताई जा रही है।

योजना की पारदर्शिता पर सवाल: ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत ने इस कार्य के लिए न तो पूर्व सूचना दी और न ही

किसी प्रकार की सार्वजनिक सहमति या ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिना ग्रामसभा की अनुमति के यह कार्य कैसे स्वीकृत हुआ? इसके अलावा, तालाब निर्माण के लिए चुनी गई जगह पहले से ही सार्वजनिक उपयोग की थी — ऐसे में खेल मैदान को तालाब में बदलना ग्रामीणों के अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है।

प्रशासन से जांच की मांग: ग्रामीणों ने उच्च प्रशासन से मांग



की है कि इस कार्य की जांच करवाई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मनरेगा की राशि कहाँ और कैसे खर्च की गई। साथ ही, जिन मजदूरों के नाम पर भुगतान हुआ है, उनका सत्यापन और ऑडिट कराया जाए।

सवाल उठे, जवाब नहीं: तालाब निर्माण को लेकर पंचायत और संबंधित विभागों से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी आधिकारिक बयान देने से परहेज किया।

इस घटना ने एक बार फिर

यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या ग्रामीण विकास योजनाएँ वास्तव में जनता के हित में हैं या फिर भ्रष्टाचार की नई परत बनती जा रही हैं?



टीआरएस कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले में 1567 युवाओं को मिला रोजगार



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। युवा संगम कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थाओं में रोजगार मेलों का आयोजन कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल के मार्गदर्शन में शासकीय टीआरएस कॉलेज रीवा में किया गया। जिला रोजगार अधिकारी उप संचालक अनिल दुबे ने बताया कि इस मेले में 2205 आवेदकों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 1567 युवाओं का चयन किया गया। मेले में शामिल 40 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए।

मुख्य याजाकी इंडिया लि. हरियाणा में 66, लेन्सकार्ट इंडिया बिलहरी राजस्थान में 152, एनबीएम पीजी भिवाड़ी राजस्थान में 69, एमआरएफ दहज में 64, टाटा ऑटोकार्प पैन्स ग्रुप लि. अहमदाबाद में 7,

फ्रिन्स सीमेंट लि. सतना में 7, अपोलो टायर्स लि. बड़ौदा गुजरात में 11, औरंगाबाद ऑटो एक्सिलरी प्रा. लि. वालुज में 13, और अन्य कंपनियों ने भी युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार मेले में मिग्मा पैक्ट्रॉन प्रा. लि. इंदौर में 32, आयसर ट्रक एण्ड बस पीथमपुर धार इंदौर में 25, लार्सन एण्ड दुब्रो अहमदाबाद गुजरात में 30, बजाज मोटर लिमिटेड औरंगाबाद में 23, और अन्य कंपनियों ने भी युवाओं का चयन किया। रोजगार मेले के सफल आयोजन में जिला रोजगार कार्यालय, शासकीय टीआरएस कॉलेज, एकेएस यूनिवर्सिटी सतना, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, आईटीआई, स्वास्थ्य विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रेक्षक आज करेंगे मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा

रीवा। नगरीय निकायों तथा पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। आयोग द्वारा रीवा जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक मुन्नालाल सिसोदिया 17 अक्टूबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा करेंगे।

छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल परिसर में पहुंचकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह हादसा प्रदेश सरकार की लापरवाही और दवा माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। जहरीली कफ सिरप से मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन सरकार अब तक जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनी पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर



राजेन्द्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ पूरी तरह चरमराई हुई हैं। सरकारी अस्पतालों में न तो दवा है, न जांच की सुविधा, और अब तो जहरीली दवाओं से बच्चों की जान जा रही है। यह मध्यप्रदेश के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने चेतावनी दी

कि अगर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी।

धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने मृत बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं,

बल्कि सरकार की असंवेदनशीलता का परिणाम है। इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में बच्चों को न्याय दो, दोषियों को सजा दो, और मोहन सरकार जवाब दो जैसे नारे गूंजते रहे। अंत में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि जहरीली कफ सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए।

रीवा में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन देर तक चलता रहा, जिसमें शहर और आसपास के ब्लॉकों से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

20 साल नौकरी से नदारद रही शिक्षिका ने फर्जीवाड़ा किया, हाई कोर्ट में की सुनवाई में पकड़ी गई; पुलिस ने एफआईआर दर्ज की

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। 20 साल से नौकरी से गायब रही महिला शिक्षिका सेवा में लौटने की मांग लेकर अचानक रीवा मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। विभाग ने ज्वाइनिंग से इनकार किया तो शिक्षिका ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई के दौरान उसके बीमारी और फिटनेस सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा सामने आया, जिससे कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और रीवा एसपी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। आदेश के तहत रीवा पुलिस ने आज (गुरुवार) एफआईआर दर्ज कर ली।

ऐसे खुला फरेब का मामला: दरअसल, रीवा निवासी अर्चना आर्या ने याचिका में बताया कि उन्हें 2001 में शिक्षा कर्मी वर्ग-तीन के पद पर नियुक्त किया



गया था। बीमारी के कारण वे 2002 से 2018 तक सेवा से अनुपस्थित रहीं। 2018 में उन्होंने विभाग में दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए, पहला- 2006 का अनफिट (बीमारी का) प्रमाणपत्र और दूसरा- 2017 का फिटनेस सर्टिफिकेट। उन्होंने मांग की कि इन दस्तावेजों के आधार पर उनका मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर सेवा में पुनः लिया जाए, लेकिन विभाग ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद अर्चना हाईकोर्ट

पहुंचीं। **कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा:** जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि 2006 का बीमारी प्रमाणपत्र और 2017 का फिटनेस प्रमाणपत्र, दोनों पर ही रीवा मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के एचओडी डॉ. प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर हैं। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि क्या एक व्यक्ति 11 साल तक एचओडी बना रहा?

1 नवंबर को राजकपूर ऑडिटोरियम में रिदम म्यूजिकल ग्रुप का विन्ध्या म्यूजिशनन आइकॉन एवार्ड फंक्शन और शुभ दीपावली मिलन संध्या का कार्यक्रम



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। नगर की अग्रणी संस्था रिदम म्यूजिकल ग्रुप का विन्ध्या म्यूजिशनन आइकॉन एवार्ड फंक्शन आगामी 01 नवम्बर को कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का सह-आयोजन हिन्दू धर्म परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें शुभ दीपावली मिलन के अवसर पर संस्था द्वारा यादगार प्रस्तुतियों के लिए गीत-संगीत-नृत्य कलाकारों एवं उपस्थित नगरवासियों द्वारा सामूहिक दीप प्रज्ज्वलन कर खुशियां बांटी जाएंगी। रिदम परिवार के अध्यक्ष डॉ. विनोद तिवारी, उपाध्यक्ष अवनीश शर्मा, और महासचिव पियूष मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में पहली बार विन्ध्यक्षेत्र के समस्त संगीत प्रेमियों, वरिष्ठ गायकों एवं म्यूजिशियनों को एवार्ड 2025 देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी कलाकारों को परिवार सहित आमंत्रित करने के लिए संस्था द्वारा सघन संपर्क किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में हिन्दू धर्म परिषद के संस्थापक नारायण डिगवानी, संयोजक सुमित

माँजवानी, संरक्षक अवधेश श्रीवास्तव, इंजी. राजेश श्रीवास्तव, डीपी सिंह परिहार, अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, युवा शाखा अध्यक्ष विकास सेन आर्यन, और महिला शाखा अध्यक्ष ममता नरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में गणमान्य अतिथियों और संगीत में रुचि रखने वाले नागरिकों को बुलाया जाएगा। डॉ. विनोद तिवारी ने बताया कि पहली बार हो रहे इस आयोजन की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। यह आयोजन उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की प्रेरणा एवं आग्रह से किया जा रहा है। इसमें संगीत वाद्यों पर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करने और गायकों को अभूतपूर्व संगत प्रदान करने वाले संगीतकारों, उस्तादों, और गुरुओं को सार्वजनिक सम्मान देने का निर्णय लिया गया है।

संस्कृतिधानी विंध्य क्षेत्र में तानसेन जैसे गायकों ने गुरुदीक्षा हासिल कर समूचे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की है। इस आयोजन के माध्यम से नृत्य कलाकारों को भी विशाल मंच प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की परिकल्पना की गई है।

ग्राम पंचायत डिहिया पड़ान सरपंच ने पति, ससुर और देवर को बनाया वेंडर, पंचायत के राशि का किया खुला दुरुपयोग

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिला अंतर्गत जनपद पंचायत नईगढ़ी से एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत डिहिया पड़ान की सरपंच वंदना पाण्डेय और सचिव रामलाल साकेत पर आरोप है कि उन्होंने पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने सगे संबंधियों के खातों में पंचायत की राशि का भुगतान किया है।

पंचायत दर्पण 5.2 पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, दिलराज पाण्डेय (पति) के खाते में 35,000 रुपये, तेजेश्वर प्रसाद पाण्डेय (चाचा ससुर) के खाते में 30,000 रुपये, और संजय



कुमार पाण्डेय (देवर) के खाते में 12,000 रुपये का भुगतान 21 अगस्त और 09 सितम्बर को किया गया है। यह स्पष्ट रूप से पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 का उल्लंघन है, जो कहता है कि सरपंच स्वयं या अपने परिजनों के माध्यम से पंचायत निधि का व्यय नहीं कर सकता।

भ्रष्टाचार की अति तब हुई जब तीन महीने में 74,550 रुपये की मिठाई राज किशोर पटेल नाम से संचालित राजू मिष्ठान भंडार से आहरित की गई। ग्रामवासियों का कहना है कि पिछले चार महीनों में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें इतनी मिठाई की आवश्यकता पड़ी हो, जिससे यह फर्जी बिलिंग का

परियोजना अधिकारी के साथ हुई लूट का रीवा एसपी ने किया खुलासा

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग मनगवा प्रतिभा शर्मा और थाना प्रभारी मनगवा निरीक्षक गजेन्द्र सिंह धाकड़ की उपस्थिति में 11 अक्टूबर को हुई लूट का खुलासा किया गया।

रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि यह लूट की घटना परियोजना अधिकारी दीपक मिश्रा के साथ हुई थी। इस मामले में एसडीओपी मनगवा प्रतिभा शर्मा और थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह धाकड़ को प्रयासों से चार नफर आरोपियों को



गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लूटे गए माल को भी बरामद किया, जिसमें नगदी, मोबाइल, कार की

चाबी, घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार, 1 नग देशी पिस्टल, 2 नग कट्टा और 16 नग जिन्दा कारतूस शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 12 अक्टूबर 2025 को फरियादी दीपक मिश्रा, जो कि 46 वर्ष के हैं, अपनी कार

मारुति सुजुकी एसएक्स से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर जबलपुर से त्योंथर जा रहे थे। रात करीब 10:30 बजे एनएच-30 रोड ग्राम समान, नहर के पास बिना नंबर की लाल रंग की ब्रेजा कार में सवार चार व्यक्तियों ने उनकी कार को रोककर पिस्टल और कट्टा दिखाकर लूटपाट की।

लूट के दौरान आरोपियों ने दीपक मिश्रा से नगद, मोबाइल, एट्रीएम, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिए। घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने एक टीम गठित की और आरोपियों की तलाश शुरू की।

पुलिस ने नौशад अहमद, मो. फैजान, गुलजार उर्फ

रिजवान खान और दिलशाद अली को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और प्रयागराज के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मामले में सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

बंधक बनाकर लूट करने वाले चार चोर गिरफ्तार

रतलाम, एजेंसी। रावटी थाना अंतर्गत बंधक बनाकर लूट करने व चोरी की दो अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने गुरुवार को पकड़ लिया। चोर गांव के रहने वाले निकले। सीसीटीवी नहीं होने से पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आसपास पृच्छाछ की तो चोरों को पता चल पाया। पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा है जिनमें दो नाबालिग हैं।

सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल ने बताया कि 2 अक्टूबर की रात अज्ञात आरोपियों ने रवि डामर निवासी रानीसिंग के घर की दीवार लोहे के सरिये से तोड़कर घुसे थे। परिवार को बंधक बनाकर धमकाते हुए 60 हजार रुपए नगद, चांदी के आभूषण (कड़ा, हाथफूल, मंगलसूत्र, बिछड़ी आदि) चोरी कर लिए थे।

इसी प्रकार 5 अक्टूबर की रात नीलेश सोनी की दुकान का शटर उचकाकर सात हजार नकद एवं चांदी की झुमकियां चोरी की। चार दिन बाद फिर 9 अक्टूबर को गांव में मुकेश मालीवाड़ और सुनील मचार की गुमटियों के ताले तोड़कर नकली

दो नाबालिग शामिल; पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया



आभूषण, कपड़े व अन्य सामग्री चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। थाना रावटी में अलग-अलग केस दर्ज कर चोरों की तलाश के लिए टीम बनाई गई।

चोरी का सामान भी जब्त

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिंगर प्रिंट टीम, सायबर

टीम एवं थाना रावटी की संयुक्त कार्रवाई के तहत घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी दीपक मंडलोई, सैलाना थाना प्रभारी सुरेश गडरिया के नेतृत्व में जांच टीम द्वारा जमीनी पुलिसिंग, मुखबिर तंत्र एवं सतत निगरानी से संदिग्धों की पहचान की।

लगातार प्रयासों से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पृच्छाछ की तो उन्होंने अपने दो अन्य साथियों के साथ तीनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया सामान भी जब्त कर लिया है।

इन्हें किया गिरफ्तार

दो 16 वर्षीय किशोर।

इनकी रही भूमिका

चोरों को पकड़ने में रावटी थाना प्रभारी के अलावा सब इंस्पेक्टर पीएस हटीला, एमआई खान, एसएसआई गणेश शर्मा आदि समेत सायबर टीम का की भूमिका रही।

छेड़छाड़ के आरोपी के सुसाइड केस में एफआईआर युवती, उसकी बहन और जीजा ने किया था प्रताड़ित



बाद में युवक ने महिला थाने से चला गया।

विवेकानंद घाट पर मिला

था अंकित गौर का शव

एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने बताया कि जहाजपुरा निवासी अंकित गौर ने 12 अक्टूबर विवेकानंद घाट पर सुसाइड किया था। शाम को उसका शव

मिला था। 13 अक्टूबर को पोस्टमॉर्टम के दौरान जिला अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर युवती, उसकी बहन और जीजा पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।

इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच की। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी यह सामने आया कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था। पुलिस ने बताया कि जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उनमें जमानत नहीं मिलती। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को केंद्रीय जेल भेजा जाएगा।

11 अक्टूबर को युवती के घर के सामने जाकर गाली गलौज करने पर परिजन ने अंकित गौर को पकड़कर महिला थाने लेकर आए थे। महिला थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया और न नोटिस दिया गया।

18 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, परिजन खेत से लौटे तो घर में फांसी पर लटकी मिली

बैतुल, एजेंसी। भदूस गांव में बुधवार शाम एक 18 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी की पहचान प्रतिभा के रूप में हुई, वह कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने गुरुवार को जिला अस्पताल में उसका पोस्टमॉर्टम कराया।पुलिस के अनुसार, घटना के समय प्रतिभा के परिजन खेत में मक्का तोड़ने गए हुए थे। जब वे घर लौटे, तो उन्होंने प्रतिभा को घर के पिछले कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।

एसएसआई प्रवीण पचौरी ने बताया कि प्रतिभा ने बुधवार



दोपहर परिजनों के साथ भोजन किया था और तब तक उसका व्यवहार सामान्य था। शाम को जब परिजन खेत से लौटे, तो उन्हें यह घटना मिली।

जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को नीचे उतारकर जिला

अस्पताल भेजा, जहां छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।पुलिस के अनुसार, आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रतिभा का एक भाई भोपाल में पढ़ाई करता है।

खेत पर करंट लगाने से किसान की मौत

रबी सीजन के लिए सर्विस लाइन ठीक करने गया था, खेती के साथ मार्केटिंग करता था

खंडवा, एजेंसी। आज (गुरुवार) एक किसान की करंट लगाने से मौत हो गई। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। वह रबी सीजन की तैयारी के बीच सर्विस लाइन को दुरुस्त करने खेत पर पहुंचा था। जहां सर्विस लाइन में एक ज्वाइंट था, भविष्य में लाइन फॉल्ट का खतरा न हो, इसलिए किसान नए सिरे से ज्वाइंट बनाने लगा। किसान को पावर ऑन है, इस बात का अंदाजा नहीं रहा और करंट ने चपेट में ले लिया।

घटना शहर से सटे नागचून ग्राम पंचायत के तहत आने वाले ग्राम बड़गांव भीला की है। किसान महावीर उर्फ गोलू राजपूत (35) अपने खेत पर गया था। परिजन के अनुसार, महावीर खेती के अलावा खंडवा की एक ईट फैक्ट्री में मार्केटिंग और पैसा कलेक्शन



का काम करते थे। महज दो एकड़ जमीन में इतनी पैदावार नहीं हो पाती कि परिवार का भरण-पोषण कर सकें, इसलिए वह खेती के

ग्रामीण पहुंचे तब तक जान चली गई, परिवार में दो बच्चे

परिजनों ने बताया कि महावीर को खेत में कुएं के पास करंट लगा था। उसी कुएं के पास से दूसरे खेतों के लिए जाने का रास्ता है। करंट लगने के बाद महावीर जब तड़प रहा था, तभी गांव का एक बुजुर्ग किसान अपने खेत पर जा रहा था। उन्होंने महावीर को तड़पते हुए देखा लेकिन न तो उनके पास मोबाइल था कि गांव में किसी को फोन लगा दें। बुजुर्ग दौड़ते-भागते हुए गांव में पहुंचा और महावीर के बारे में सूचना दी। ग्रामीण और परिजन खेत पर पहुंचे, तब तक महावीर की सांसें थम गई थीं। इधर, महावीर के परिवार में मां, पत्नी और दो बच्चे हैं। एक बेटा और बेटी है, जो मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं।

साथ मार्केटिंग करते थे। महावीर, सुबह 10 बजे ड्यूटी के लिए अपने घर से निकलते इससे पहले घर व खेती के काम निपटायें। हाल ही में खेत में सोयाबीन की फसल बोई थी, जिसमें काफी नुकसान हो गया। महावीर खेत पर सीजन की तैयारी के बीच सर्विस

लाइन को ठीक करने पहुंचा। तभी सर्विस लाइन में ज्वाइंट दिखा तो फॉल्ट के अंदेशे को भांपते हुए उन्होंने तत्काल ठीक करना उचित समझा। लेकिन इस दौरान चालू लाइन होने के चलते करंट ने उन्हें चपेट में ले लिया।



20 दिन के नवजात की मौत-आरोप बंगाली डॉक्टर ने गलत दवा दी

मुंह से ऑक्सीजन देते दिखे परिजन

छतरपुर, एजेंसी। छतरपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 20 दिन के एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने बच्चे की मौत का कारण गलत इलाज को बताया है। बच्चे को जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद भी परिजन उसे मुंह से ऑक्सीजन देकर बचाने की कोशिश करते रहे। यह देख वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। परिजनों ने एक बंगाली डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है।

जुकाम होने पर बंगाली डॉक्टर के पास ले गए थे:लखरावन गांव निवासी भारत अहिरवार ने बताया कि उनके 20 दिन के भतीजे को दो दिन से हल्का बुखार और जुकाम था। गुरुवार सुबह बच्चे की मां शिवकुमारी उसे इलाज के लिए

कोटा में एक बंगाली डॉक्टर के पास ले गईं। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवा के कुछ देर बाद ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी।

निजी अस्पताल ने इलाज से किया इनकार:हालत बिगड़ने पर परिजन तुरंत बच्चे को बाइक से एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद वे बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर अभय सिंह ने जांच के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत का कारण:वहीं, जिला अस्पताल के डॉ. अभय सिंह ने बताया कि नवजात को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

खाद के लिए रातभर लाइन में खड़े रहे किसान-सीहोर में किसान ने कहा खाद नहीं दे सकते तो जहर ही दे दो

हमें अन्नदाता से अंधेदाता बना दिया

सीहोर, एजेंसी। सीहोर जिले में किसान खाद की भारी किश्त का सामना कर रहे हैं। सहकारी समितियों के बाहर किसानों को रातभर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। घंटों की मशक़त के बाद मुश्किल से एक-दो बोरी खाद मिल पाती है।

रातभर लाइन में खड़े रहे किसान

खाद की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण रबी सीजन की बुवाई का कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों में गहरी निराशा है और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ताजा

मामला बोर्दी कलां गांव का है, जहां खाद की कमी के चलते किसान सहकारी समिति परिसर में रातभर लाइन में खड़े रहे। प्रशासनिक अव्यवस्था के बीच जब खाद वितरण शुरू हुआ, तो पुलिस जवानों को व्यवस्था संभालनी पड़ी।

किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया

किसानों का कहना है कि उन्हें खाद की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि शासन-प्रशासन इस समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकाल रहा है। किसानों

ने यह भी आरोप लगाया है कि सोसायटियों में खाद की आपूर्ति कम है, जबकि बाजार में इसकी जमकर कालाबाजारी हो रही है और व्यापारी महंगे दामों पर खुलेआम खाद बेच रहे हैं।

खाद नहीं दे सकते तो जहर ही दे दो- किसान

कुछ किसानों ने हताशा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि शासन-प्रशासन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं करा सकता, तो कम से कम सल्फास जहर ही दे दे, ताकि उन्हें रोज़मर्रा की इस जद्दोज़हद से छुटकारा मिल सके।



विहिप, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी ने निकाली शक्ति यात्रा



मंदसौर के पिपलियामंडी में सैकड़ों महिलाओं और युवतियों ने लिया भाग

मंदसौर, एजेंसी। मंदसौर के पिपलियामंडी में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप), बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने संयुक्त रूप से एक शक्ति यात्रा का आयोजन किया। पथ संचलन में सैकड़ों युवतियों और महिलाओं ने भाग लिया। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से शुरू होकर अयोध्या बस्ती, टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर और गांधी चौराहा सब्जी मंडी सहित नगर के मुख्य मार्गों से गुजरा। यात्रा का समापन वापस विद्यालय परिसर में हुआ। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

ये रहीं मुख्य अतिथि

कार्यक्रम के मुख्य मंच पर मालवा प्रांत की संयोजिका ज्योतिप्रिया शर्मा, मंदसौर विभाग की संयोजिका टीना शर्मा और सरस्वती शिशु मंदिर की अध्यक्ष बंटी भूत मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बंटी भूत ने की। इस अवसर पर मातृशक्ति जिला संयोजिका शांति रावल, प्रखंड अध्यक्ष मनोहर मनवानी, विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला और विहिप जिला सह मंत्री निलेश जैन भी उपस्थित थे।

पुलिस बल रहा तैनात

यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी और चौकी प्रभारी धर्मेश यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने पूरे मार्ग पर निगरानी रखी और यातायात व्यवस्था को संभाला। कार्यक्रम का संचालन जिला विद्यार्थी प्रमुख तनिषा डाबी ने किया, जबकि दिव्य कुमावत ने आभार व्यक्त किया।

लोडिंग वाहन डिवाइडर पर चढ़ा, बिजली पोल गिरा-चालक ने पत्ता टूटने वजह बताई,अगला टायर भी पंचर हुआ

रायसेन, एजेंसी। रायसेन-सागर मार्ग पर गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे शासकीय आदर्श कन्या स्कूल के सामने एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में नगर पालिका का एक बिजली का पोल गिर गया और एलईडी लाइट टूट गई। वाहन चालक नानालाल ने बताया कि वह उज्जैन से सिलवानी जा रहे थे। फिलहाल, नगर पालिका के कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचकर टूटे पोल को हटाकर किनारे कर चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई है।

अगला पहिया भी पंचर हुआ

लोडिंग वाहन के चालक नानालाल ने बताया, -सड़क पर जाते समय वाहन के पते टूट गए। इससे वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकरा गया। वाहन का अगला पहिया भी पंचर



हो गया था।

बिजली के पोल को हटा कर किनारे किया

नगर पालिका के कर्मचारियों ने सड़क पर गिरे बिजली के पोल को हटा कर किनारे कर दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी और वाहन स्थल से

हटाया गया।

लोडिंग वाहन चालक नशे की हालत में था

नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि लोडिंग वाहन चालक नशे की हालत में था। यही कारण है कि वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया।

90 लीटर महुआ शराब और 50 किलो लाहन जब छिंदगांव जंगल में आबकारी विभाग की कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राजनांदगांव जिले में मदिरा के अवैध निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध जांच पड़ताल एवं कार्रवाई का अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम छिंदगांव जंगल क्षेत्र में 90 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब तथा 50 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया।

प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले में मदिरा के अवैध विक्रय पर रोकथाम हेतु होटल, ढाबों और मदिरा दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। सभी वृत्त प्रभारियों को अवैध शराब विक्रेताओं, भंडारणकर्ताओं तथा सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक बिलासपुर रीजन में 5969 आवेदन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक 5 हजार 969 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 930 उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लॉट स्थापित किए जा चुके हैं। इसी तरह 628 उपभोक्ताओं को उनकी सविस्डी की राशि का भुगतान शासन द्वारा कर दिया गया है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में कार्यशालाएं और शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है।

पूर्व के पंजीकृत आवेदनों पर प्लांट स्थापना का कार्य शीघ्र: कार्यालालक निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर ने योजना के सफल और त्वरित क्रियान्वयन हेतु अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं एवं सोलर वेंडों को निर्देशित किया है कि वे सम्मिलित प्रयासों से लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है, जिन्होंने पूर्व में पंजीयन करवाया है, ताकि शीघ्र सोलर प्लॉट स्थापना का कार्य पूरा हो सके।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर ने बताया कि बिलासपुर रीजन में प्राप्त 5969 आवेदनों में से कोरबा वृत्त के 1395, बिलासपुर नगर वृत्त के 1526 तथा बिलासपुर (संचा./संघा.) वृत्त के 3048 उपभोक्ता सम्मिलित हैं। इनमें से 930 उपभोक्ताओं के घरों में सोलर प्लॉट स्थापित किए जा चुके हैं और 628 उपभोक्ता शासन की सविस्डी का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सोलर प्लॉट स्थापना के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। बिलासपुर रीजन के 21 उपभोक्ताओं के बिजली बिल अब ःजीरो बिल में परिवर्तित हो गए हैं, जिससे योजना की सफलता और उपयोगिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहनी-तिलहनी फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान दक्षःण्ड के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत गत वर्ष राज्य के 18 जिलों में 152 उपजान केन्द्र स्थापित किए गए थे। इन केन्द्रों का उद्देश्य कृषकों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों का विक्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित कराना है। कृषि विभाग खैरागढ़ के उपसंचालक राजकुमार सोलंकी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य में उत्पादित अरहर, उड़द एवं मसूर फसलों का शत-प्रतिशत उपार्जन तथा मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, चना और सरसों का 25 प्रतिशत उपार्जन किया जाता है। केन्द्र सरकार की प्रापण संस्थाएं नाफेड एवं एन.सी.सी.एफ. इस कार्य को संचालित करती हैं। कृषकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत उपज विक्रय के इच्छुक कृषक को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है, जिसमें समीपस्थ उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकता है। यदि किसी जिले में उपार्जन केन्द्र सीमित हैं, तो कृषक अन्य जिले के उपार्जन केन्द्र में भी अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीफ में उत्पादित मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीदी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इसके उपरांत खरीफ की अरहर एवं रबी की चना, मसूर एवं सरसों फसलों का उपार्जन किया जाएगा। प्रत्येक अधिसूचित फसल की उपार्जन अवधि 90 दिवस निर्धारित की गई है। आवश्यकता पड़ने पर जिले के कलेक्टर के प्रस्ताव पर इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

यह योजना न केवल किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में सहायक है, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उपज के अधिक मूल्य प्राप्ति में भी सहायक है। इससे फसल विविधिकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य एक फसलरहित कृषि से बहुफसलीय कृषि की ओर अग्रसर होगा। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला उप संचालक कृषि से जिलेवार फसल रकबा, संभावित उत्पादन, उपार्जन एवं भंडारण केन्द्रों के निर्धारण संबंधी जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर उपार्जन केन्द्र निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही, कृषकों को योजना के लाभ से अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से बिट्टू का संवर रहा भविष्य

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे श्रमिक के पुत्र बिट्टू कुशवाहा ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे जिले के नाम प्रवेशन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना ने श्रमिक परिवारों के सपनों को नई दिशा दी है। बिट्टू कुशवाहा ने कक्षा 10 वीं के परीक्षा में राज्य में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई तथा नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत बिट्टू कुशवाहा लाभान्वित हुआ।

बिट्टू कुशवाहा को मिला नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड कुसुमी के ग्राम नवाडीह निवासी कमलेश कुशवाहा जो त्रिम विभाग में पंजीकृत श्रमिक है, जो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहा। अपनी सीमित आय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बेटे की शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी। परिणामस्वरूप बिट्टू कुशवाहा ने अपनी मेहनत और लगन से कक्षा 10 वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप 10 (मेरिट) में अपनी जगह बनाई तथा नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत बिट्टू कुशवाहा लाभान्वित हुआ। उन्हें कुल 2 लाख रुपये की शैक्षणिक सहायता राशि प्रदान की गई। जिसमें 1 लाख रुपये वाहन के लिए एवं 1 लाख रुपये शिक्षा सहायता राशि दी गई। इस आर्थिक सहयोग से बिट्टू उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर सकेगा।

श्रमिक परिवार के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने अनेक योजनाएं: बिट्टू ने बताया कि मेरे पिता ने हठशा मेहनत करना सिखाया है और वे कहते हैं कि निरंतर कोशिश करने वालों को कभी निराशा नहीं होना चाहिए। बिट्टू कहता है कि मेहनत करना पिता से सीखा तो वहीं सपनों को पूरा करने का उम्मीद शासन की योजनाओं से संभव हो रही है। वह बताता है कि वाहन के लिए प्राप्त राशि से उसने स्कूटी खरीदा और आगे नोट की तैयारी कर रहा है, ताकि चिकित्सक बनकर क्षेत्र में जाकर अपनी सेवाएं दे सके। बिट्टू के पिता श्री कमलेश कुशवाहा भावुक होकर कहते हैं कि पहले लगता था ।

युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित करने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार 150 यूनिटी मार्च केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का आयोजन, देशभर में होंगे विविध कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)।

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रव्यापी सरदारख150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से देशभर के युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधायक श्री नवीन मारकंडेय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक तर्जुना सलाम भी इस दौरान मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2025 को



सरदारख150 यूनिटी मार्च (Sardar@150 nit 4 March) की शुरुआत की है। यह भारत सरकार और 'मेरा युवा भारत' (MY Bharat) की पहल है, जो लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत

प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सरदारख150 यंग लीडर्स प्रोग्राम (Sardar@150Young Leaders Program) शामिल हैं। इसमें सरदारख150 यंग लीडर्स प्रोग्राम के 150 विजेताओं को राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरदारख150 यूनिटी मार्च के तहत आगामी 31 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक जिला स्तरीय पदयात्राएं होंगी। हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में तीन दिनों तक 8डू10 किमी लंबी पदयात्रा होगी। पदयात्रा से पहले स्थानीय लोगों को प्रेरित करने के लिए स्कूल, कॉलेजों में अलग-अलग निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर संगोष्ठी, नुकड़ नाटक जैसी प्री-इवेंट गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनके साथ ही युवाओं के बीच नशामुक्त भारत शपथ, संस्थानों में स्वदेशी मेलों का आयोजन, गर्व से स्वदेशी संकल्प भी

दिलाएं जाएंगे।

श्री साव ने बताया कि राष्ट्रीय पदयात्रा के अंतर्गत 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक सरदार पटेलजी के जन्म स्थान करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया तक 152 किमी की पदयात्रा निकाली जाएगी। रास्ते में पड़ने वाले गाँवों में सामाजिक विकास के कार्यक्रम होंगे, जिनमें मेरा युवा भारत (MY Bharat), एनएसएस के स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स और युवा लीडर भाग लेंगे। इस दौरान 150 पड़वों पर सरदार पटेल के जीवन पर विकसित भारत की प्रदर्शनी और भारत की विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरदारख150 यूनिटी मार्च के तहत सभी पंजीकरण और गतिविधियाँ MY Bharat Portalhttps://m4bharat.go1.in/page s/unit_4_march पर हो रही हैं। श्री साव ने सभी युवाओं से इस ऐतिहासिक पहल से जुड़कर सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ा, धान के रकबे में हुई कमी किसानों में बढ़ा भरोसा-अब दलहन, तिलहन फसलों की ओर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में विगत वर्ष धान की बंपर पैदावार के बावजूद अब किसानों में पारंपरिक फसलों के साथ अन्य फसलों की ओर रुझान बढ़ने लगा है। कोरिया जिले के किसान अब धान के अलावा दलहन, तिलहन की खेती में भी रुचि ले रहे हैं, जिससे फसल विविधीकरण की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। किसानों में अब दलहन, तिलहन फसलों की ओर भरोसा बढ़ा है। कृषि विभाग कोरिया से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2024-25 में जिले में 33 हजार 842 हेक्टेयर में धान की बुवाई की गई थी, जबकि वर्तमान खरीफ वर्ष 2025-26 में 32 हजार 920 हेक्टेयर में धान बोया गया है। इस प्रकार 922 हेक्टेयर क्षेत्रफल में (2.75 प्रतिशत) कमी दर्ज की गई है।

जिले में दलहन और तिलहन फसलों के रकबे में उल्लेखनीय



वृद्धि हुई है। विगत वर्ष 9 हजार 194 हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई थी, जबकि इस वर्ष यह बढ़कर 9 हजार 730 हेक्टेयर हो गई है यानि 536 हेक्टेयर (5.82 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 में 1 हजार 874 हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुवाई हुई थी, जबकि वर्तमान वर्ष में यह बढ़कर 2 हजार 272 हेक्टेयर तक पहुँच गई है यानी तिलहन की खेती में 398 हेक्टेयर (21.23 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई है।

मूंगफली फसल की बात करें तो इसमें भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 933

ग्राम पंचायत चैनपुर में पोषण माह का समापन गोदभराई और अन्नप्राशन कार्यक्रमों ने दिया संतुलित आहार व स्वस्थ जीवन का संदेश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। ग्राम पंचायत चैनपुर में आज पोषण माह का समापन समारोह बड़े उत्साह और सहभागिता के साथ मनाया गया। एक माह तक चले इस अभियान ने न केवल माताओं और बच्चों में पोषण के महत्व को उजागर किया, बल्कि पूरे ग्राम को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुधार की दिशा में नई चेतना भी दी।

दीप प्रज्वलन से हुई शुरुआत: कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि सरपंच मीना कुमारी ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। उन्होंने उपस्थित माताओं को संतुलित आहार अपनाने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की।



उपस्थित रहे जनप्रतिनिधि व अधिकारी: समारोह में उपसरपंच मदन, पंच राजकुमारी, बबली सिंह, हीराकली, सेक्टर सुपरवाइजर शिल्पा अग्रवाल और स्वच्छता समन्वयक प्रभा पयासी विषय रूप से उपस्थित रहें। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी शामिल हुईं।

पोषण माह की झलकियाँ: सेक्टर सुपरवाइजर

शिल्पा अग्रवाल ने 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक चले पोषण माह की गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस अवधि में गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान, पौष्टिक आहार संबंधी गोष्ठियाँ और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को समाप्त करना और

स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना रहा।

गोदभराई और अन्नप्राशन ने बढ़ाया उत्साह: समापन अवसर पर 8 गर्भवती माताओं को गोदभराई की गई। इनमें राजकुमारी, पूनम, कमल, अनू, सरिता, उर्मिला, सुनैना और पूर्णिमा शामिल थीं। वहीं 4 शिशुवती माताओं – बसंत, प्राची, सुनैना और रानी – के बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। इन अवसरों पर माताओं को बच्चों के भोजन में संतुलित आहार और विशेषकर मुन्गा भाजी को नियमित रूप से शामिल करने की सलाह दी गई।

सामाजिक संदेश – बाल विवाह मुक्त पंचायत: कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक स्वर से अपने पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की शपथ ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू राजधानी में राज्योत्सव के शुभारंभ के साथ नई विधानसभा भवन का होगा लोकार्पण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 01 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड :शांति शिक्षा-का शुभारंभ और सत्य साईं हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे। अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पिंगुआ ने कहा कि



उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास में महेनजर टैफिक प्लान और पार्किंग की व्यवस्था कर ली जाए। इसी प्रकार राज्योत्सव मेला स्थल और अन्य कार्यक्रमों के स्थल पर पार्किंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि

नया रायपुर के चौक-चौराहों को व्यवस्थित और सौंदर्यकरण कर ली जाए। राज्योत्सव मेला स्थल में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए को सेक्टरों में बांटकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कार्यक्रम के दौरान सतत रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी

रखी जाए। इसी प्रकार साउंड सिस्टम उच्च गुणवत्तायुक्त हो। साथ ही दूर संचार विभाग के अधिकारियों को संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने तीन विशाल डोम बनाएं जा रहे हैं। जिनमें 60 एलईडी स्क्रीनिंग लगाए जाएंगे।

मेला स्थल पर लोगों बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के प्रवेश के लिए दो द्वार होंगे। एक द्वार विभागीय प्रदर्शनी के लिए होगा। विभागीय प्रदर्शनी में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के नजदीक ही डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेला स्थल पर प्रधानमंत्री आवास का मॉडल भी बनाया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्योत्सव मेला स्थल के दोनों तरफ 20-20 हजार वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य शहरों से रायपुर पहुंचने वाले मार्गों पर भी पार्किंग, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा रही है। राज्योत्सव मेला स्थल पर 300 शौचालय बनाए जाएंगे।